टायर-ट्यूब के उपभोक्ताओं को निश्चित दाम से काफी अधिक दाम देने पर भी वे वस्तुयें उन्हें नहीं मिलतीं। चोर-बाजारी का बाजार भी गर्म है। फलस्वरूप ट्रकों, बसों आदि के मालिकों में घोर असन्तोष है। अत: सरकार से मेरी मांग होगी कि वह इन बातों की ओर ध्यान भी दे ताकि आप जनता पर दिनो-दिन बढ़ रहे बोझ कम हो सकें और टायर-ट्यूब सस्ते मूल्य पर आसानी के साथ मिल सकें।

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Nationalisation of this Company is a welcome measure. But I criticise the Government on a different point that this work should have been done earlier. But they are doing it so late.

So far as workers' participation is concerned, that must be done. Government must think of workers' welfare. Therefore, I strongly demand that workers participation in the management must be there.

Import of raw rubber is a very dangerous policy. On imported rubber customs duty has also been reduced. This is going to do basic harm to the indigonous rubber growers, specially from Kerala. That is why I want that this kind of a thing must be stopped and indigenous production of rubber must be encouraged.

So far as the appointment of the Commissioner for compensation is concerned I would liko to say one thing that the Commissioner has been given wide powers. He should not have been given so much power. At the samo time, the time limit should have been specified to settle the claims which has perhaps not been done in the Bill and, therefore, I would suggest to the Hon. Minister that if he can do something in this matter, he should try to do it.

I would like to criticise the Government for giving Rs. five crores as compensation to the mill owners. This also is a very bad step which has been taken by the Government.

Finally, I would again reqquset the Hon. Minister that he must ensure the participation of workers in the management.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : Sir, I have noted all that the Hon. Members have said.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

— — —

15.06 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF THE PREVENTION OF DAMAGE TO PUBLIC PROPERTY ORDINANCE

AND

PREVENTION OF DAMAGE TO PUBLIC PROPERTY BILL

MR. DEPUTY SPEAKER : Now we take up items No. 8 and 9. These two items are taken together regarding Statutory Resolution and also the Bill for consideration and passing by Shri Venkatasubbaiah, Dr. Subramaniam Swamy absent, Shri Suraj Bhan absent, Shri N. K. Shejwalkar.

SHRI N. K. SHEJWALKAR (Gwalior) : Sir, I leave it to Mr. Jatiya to open it.

MR. DEPUTY SPEAKER : That is all right but we must call the names according to priority. Shri Indrajit Gupta absent, Shri K. A. Rajan absent, Shrimati Geeta Mukherjee absent. Now Mr. Satyanarayan Jatiya. I must

go according to priority. Not becauso Mr. Shejwalkar leaves it to you but according to priority Jatiya has got it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : He will speak in Sanskrit, Sir.

MR. DEPUTY SPEAKER : He can speak in Sanskrit also but I do not think their is simultaneous arrangement for translation of Sanskrit. He must give notice. If he gives notice, we can arrange.

SHRI SATYANARAYAN JATIYA (Ujjain) : Sir, I beg to move :

> "This House disapproves of the Prevention of Damage to Public Property Ordinance, 1984 (Ordinance No. 3 of 1984) promulgated by the President on the 28th January, 1984".

15.07 hrs.

[SHRI N. K. SHEJWALKAR *in the Chatr.*]

सभापति महोदय, यह जो अध्तादेशों की सरकार इस देश में है, यह अनेक प्रकार से संविधान की, प्रजातन्त्र की और इस संसद की गरिमा को ध्यान में न रखते हुए काम करने की आदी हो चुकी है और इस प्रकार से हमारे बार-बार कहने का जब कोई असर नहीं हुआ, तो यह निरनुमोदन का संकल्प लाया गया। बार-बार कहने का सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता है, पत्थर पर तो असर हो जाता है लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं होता।

रसरी आवत जात ते
सिल पर परत निशान।

किन्तु सरकार पर कोई निशान नहीं होता और जनता की भावनाओं को समझने का ये कोई प्रयास नहीं करते, ऐसा तो मैं नहीं कहता किन्तु आप की बात से जंचता नहीं है। संवैधानिक संसदीय प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि आप इस को करते, तो ज्यादा बेहतर होता। यह जो अध्यादेश लाया गया है, उन का उद्देश्य तो उपयोग पर निर्भर है किन्तु जो उपाय आप कर रहे हैं, वे उपाय पर्याप्त नहीं हैं। पूरा विचार कर के यह विधेयक नहीं लाया गया है और यदि आप पूरा विचार कर के लाए होते, तो आई०पी०सी०, भारतीय दंड विधान संहिता में उपाय हैं, उन उपायों पर विचार कर के इस विधेयक को लाते। पब्लिक प्रोपर्टी, जिसे सरकारी सम्पत्ति कहते हैं, उसकी सुरक्षा करने वाला यह मामला है, राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा करने वाली यह बात है और इस बात पर कहीं भी दो मत नहीं हो सकते लेकिन हमारे आई०पी० सी० के अन्दर जो धाराएं हैं, जिन का उल्लेख उसमें किया गया है जैसे कि धारा 425 है, 429, 430, 431 से 435 तक हैं, उन सारी धाराओं के अन्तर्गत यदि कोई पब्लिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे दंड दिया जा सकता है। अब यह कठोर होगा, ज्यादा होगा, वह बात दूसरी है लेकिन कुल मिलाकर राष्ट्रीय सम्पत्ति के बारे में जिस प्रकार से आप सोचते हैं, दूसरे लोगों की जो निजी सम्पत्ति है, उसके बारे में आप ने क्यों नहीं सोचा। जो राष्ट्रीय सम्पत्ति है, ठीक है, उस सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किन्तु जहां सरकारी संपत्ति, राष्ट्रीय सम्पत्ति का महत्व हो सकता है, वहां जो गैर-सरकारी सम्पत्ति है, जो लोगों के परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से और पसीने की कमाई से अर्जित की जाती है, उस का नुकसान क्या बर्दाश्त

किया जा सकता है। इसलिए मैंने यह कहा है। कुल मिलाकर सारी संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है। (व्यवधान)

सब को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए चाहे वह प्राइवेट प्रापर्टी हो या राष्ट्रीय संपत्ति हो। लेकिन आपके काम करने का तरीका ठीक नहीं है। मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की। आज भी ब्रिटिश पद्धति के माध्यम से काम कर रहे हैं। आज का जो शासक वर्ग है, प्रशासक वर्ग है उसके अन्दर देशवासियों के प्रति अपनेपन का भाव नहीं है। गलत काम जो भी करे वह गलती मानी जानी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला चाहे जो भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर कोई देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं मानता, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वह दोषी है। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ वही दोषी है। आज देश का जो वातावरण है, क्या वह दोषी नहीं है। आज आसाम और पंजाब में जो हो रहा है उससे इस देश में कैसा वातावरण बन रहा है? मुझे समाचार मिला है कि उज्जैन के एक बैंक कर्मचारी की हत्या कर दी गई है जिससे वहां के कर्मचारियों में भय और आतंक व्याप्त है। इनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। बैंक कर्मचारी इस बात का विरोध कर रहे हैं। रोजाना बैंकों में डकैतियां हो रही हैं। क्या यह राष्ट्रीय संपत्ति नहीं है। क्या आप राष्ट्रीय संपत्ति और जनता की संपत्ति में कोई विभेद करना चाहते हैं।

आज देश में चारों तरफ असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है। मध्य प्रदेश में डाकू रमेश मिकरवारके लगातार अपराध कर रहा है। सरकारी संरक्षण उसको प्राप्त है। इसलिए उसको पकड़ा नहीं जाता। लोगों को लूटा जाता है और किडनैप किया जाता है। उनसे फिरौतियां मांगी जाती हैं। यह काम हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए सरकार को क्या चिंता है।

कानून बनाने से और उपदेश देने से काम नहीं होगा। कानून का पालन कैसे होगा। जो स्वयं कानून का पालन नहीं करेगा वह दूसरों को पालन करने के लिए उपदेश कैसे दे सकता है। सब लोग शिखर की तरफ देखते हैं, गुबज की तरफ देखते हैं। नींव मजबूत होनी चाहिए और शिखर सुन्दर होना चाहिए। प्रशासन तंत्र हमारी नींव है जो आज खोखली हो चुकी है। उससे हमको कोई मदद नहीं मिलती। आज आम आदमी सुरक्षित नहीं है। कमजोर वर्ग, हरिजनों की सुरक्षा की बात तो सोची ही नहीं जा सकती। जिस तरह से नियम और कानून बढ़ रहे हैं, उसी तरह से असुरक्षा भी बढ़ती जा रही है। आप हर दिन नया कानून लेकर व्यवस्था का उपाय ढूंढ रहे हैं। ऊपर से मरहम पट्टी करने से उपचार नहीं होगा। इसके लिए कौन सी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, यदि सरकार ने इस पर विचार किया होता, या पुनर्विचार करके सारी बात को सोचा होता तो ज्यादा अच्छा होता। आज यह बात नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के राजभवन का वाकया यहां आया, राज्यपाल के व्यवहार को यहां सुनाया गया कि हरिजनों के बारे में उनकी क्या धारणा है।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Sir, I strongly object to it. The objection is to the discussion on the conduct of the Governor. That should not be allowed.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : यह बात सारी प्रकाशित हो चुकी है। इस सदन में उस पर चर्चा हो चुकी है। सवाल उठाया जा चुका है।

**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। यह बड़े दुःख की बात है।

श्री जगपाल सिंह : इन्डियन कांस्टीट्यूशन की शपथ जिसने ली हो और उसी कांस्टीट्यूशन का वह विरोध करे, ऐसे आदमी को रहने का कोई हक नहीं है।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : You can discuss it only in the form of a Resolution. (*Interruptions*)

SHRI JAGPAL SINGH : It is also against the traditions and against the soul of the Indian Constitution.

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं मानता हूं कि राज्यपाल की गरिमा रहनी चाहिये। किन्तु जिस प्रकार का व्यवहार आज देखा जा रहा है उसके कारण लोगों के मन में असंतोष पैदा होता है। राज्यपाल पर टीका नहीं की जानी चाहिये यह मैं मानता हूं। किन्तु इस प्रकार का जो लोग व्यवहार करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिये। वह भी हमारे देश के नागरिक हैं, यह बात अलग है कि उन्हें कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : हमारी परंपरा के खिलाफ है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): **

आपकी पम्परा के खिलाफ है।**

(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I think, anything which is not proper will not go on record.

श्री सत्यनारायण जटिया : वह जुल्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जुल्म करने वाले को छूट दे दी जाती है, यह बात ठीक नहीं है। गुनाह को पनाह देना ठीक नहीं है चाहे कोई भी करता हो। गुनाहगार को सजा देना यह संविधान की मंशा है।

सभापति महोदय : अब आप बिल पर बोलें।

श्री सत्यनारायण जटिया : आपका जो इरादा और नीयत है उसके अनुसार काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। सिद्धान्त कितने ही अच्छे क्यों न हों, लेकिन उनके क्रियान्वयन के लिये जो दृढ़ संकल्प चाहिये उसकी आवश्यकता है। सरकार का संकल्प मजबूत हो, लोगों को सुरक्षा मिले, राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा हो यह नीति ठीक है। लेकिन जिनके भरोसे उपाय करते हैं। वह ठीक नहीं है।

आज मजदूरों की आवाज उठा कर इस प्रकार की बात करते हैं, उन सदस्यों को सुरक्षा नहीं है, उनकी बात सुनने का आपको अवसर नहीं है। जो सदन के सदस्य हैं इस नाते अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो कैसे काम चलेगा। इसलिये एक सिलसिलेवार विचार होना चाहिये। पूरे राष्ट्रीय नीति की बात यदि करते हैं तो कौन-सी बात कहां होनी चाहिये, कानून का पालन किस प्रकार से किया जाना चाहिये, कौन कराने वाला है, यह बात देखी जानी चाहिये। इसलिये जो प्रशासन

**Not recorded.

का रवैया है ब्रिटिश हुकूमत के तरीके का उसको भारतीय प्रणाली के आधार पर बदलें तब काम होगा।

गलत बात यदि कोई करता है तो उसको रोकना चाहिये। छात्रों में जो असंतोष होता है वह इसलिये है कि उनकी बातें कोई नहीं सुनता है। जब तक राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुक़सान न पहुंचायें तब तक सरकार भी उनकी बात नहीं सुनती है। यह तरीका ठीक नहीं है। सरकार इतनी निष्ठुर हो गई है कि वह लोगों की बात नहीं सुनती है। अपनी राजनीतिक योजनाओं को पूरा करने के लिये सरकार सारा समय लगाती है तो फिर सरकार और राजनीतिक दलों में कोई अन्तर नहीं रह जाता है। जो बात कलकत्ते में गलत है वह सभी जगह गलत है। लेकिन सरकार का जो रवैया है वह दोहरा है। किसी विरोधी पार्टी की सरकार के क्षेत्र में जो आप करें वह तो ठीक, और अगर वही काम कांग्रेस सरकार के क्षेत्र में और दूसरे दल करें तो गलत, यह तरीका ठीक नहीं है।

प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से जो विधेयक लाये हैं और अध्यादेश लाये हैं वह ठीक नहीं है, आर्डिनेंसेज के बारे में अनेक प्रकार के वायदे आप करते रहे हैं। मेरा यह कहना है कि :

"लगा नहीं सके बाग,
सब्ज बाग दिखाये,
नारों, वादों के भरोसे
लोगों को रिझाये,
बुलन्द वादों की बस्तियां
ले कर क्या करेंगे,
हमें हमारी जमीन दे दो,
आसमां ले कर क्या करेंगे।

इसलिये यह जो सारे आपके इरादे हैं, वायदे हैं, निर्णय हैं इनको कार्यान्वित करने के लिये जब तक आप उपाय नहीं करते, समुचित रूप से पूरा-पूरा विचार नहीं करते, तब तक आपका मन्तव्य पूरा नहीं होगा और आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

इसलिए जो विधेयक लाया गया है, इसकी मंशा सही है किन्तु इसको क्रियान्वित करने के लिये आपके पास उपाय ठीक नहीं इसीलिये मैंने अपना यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : I beg to move :

> "That the Bill to provide for prevention of damage to public property and for matters connected therewith; as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

I have got the greatest respect for my friend Shri Jatiya. His speech on this Bill would have been more relevant had he participated in the Budget and other items.

Public property, particularly buses, telephones, railways, Government building, etc. are the main targets of attacks during riots, bandhs or other agitations. In the past there has been a very large number of cases of damage to public property by anti-social elements and other persons, on such occasions.

The basic law relating to damage to property and punishment for causing such damage is contained in Chapter XVII of the Indian Penal Code under the head "Mischief". The punishment for the offence of mischief is graduated according to the nature of the offence as well as the manner in which damage is caused. This law does not make

[Shri P. Venkatasubbiah]

any distinction between private and public property.

Faced with the need for curbing vandalism and damage to public property, some States like Tamil Nadu and Kerala have adopted special legislation which makes a distinction between public property by providing for deterrent punishment for causing willful damage to public property while in most States only the basic law contained in the Indian Penal Code is available.

Riots, bandhs and agitations at the slightest pretext seem to be the order of the day. Public property is a national asset and damage to it is a national loss. It was considered necessary to make immediate provision for deterrent punishment for causing damage to public property. Accordingly, on 28th January, 1984, the President promulgated the Prevention of Damage to Public Property Ordinance, 1984. This Bill seeks to replace that Ordinance.

Except for the provision to repeal the Ordinace and some necessary verbal changes, the Bill is identical to Ordinance. "Public property" has been defined as meaning any property, whether immovable or movable (including any machinery) which is owned by, or in the possession or control of the Central Government, or any State Government, or any local authority, or any Corporation established by, or under a Central, Provincial or State Act, or any company as defined in Section 617 of the Companies Act, or any such other institution, concern or undertaking financed wholly or substantially by funds provided directly or indirectly by the Central Government or by one or more State Governments, as the Central Government, may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf. Under this proposed law a person who commits mischief in respect of any public property, being any building, installation or other property used in connection with the production, distribution or supply of water, light, power or energy, or any oil installations, sewage works, mine or factory or means of public transportation or tele-communications, etc., is punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months, but which may extend to five years and with fine. Mischief in respect of any other Public property will be punished with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine.

However, for a person who commits mischief against any type of public property by means of fire or explosive substance, the punishment shall be stiffer, namely, rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but may extend to 10 years or fine. No person accused or convicted of any offence under this law shall, if in custody, be released on bail or on his own bond without giving the prosecution an opportunity to oppose application for such release.

This is a very simple Bill and these measures were generally welcomed in the other House also when I moved. So, I commend this Bill to this august House for its approval.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri) : Does the definition of "public property" include trust' property such as Temples, Gurudwaras and Majlis ? *(Interruptions)*

SHRI P. VENKATASUBBIAH : Private property is already in the Indian Penal Code. I will tell you.

MR. CHAIRMAN : I do not know whether I can ask a question. But for the elucidation of the House, may I ask ? The personal car of a person who is a Director of the company is burnt down. Then, nothing happens. But if the car so burnt is owned by the company, then it becomes a serious offence. How do you define ?

SHRI P. VENKATASUBBIAH : Burning of a car itself is an offence

even if it is a private property. It comes under the provision of mischief.

MR. CHAIRMAN : I am referring to the seriousness which is being tried to be given by this Bill. I mean, the gravity of the offence. The car comes from the mill. Nobody knows whose car is this. If the car is that of the company, it is a grievous offence. But if it is of the Director, it is not.

SHRI E. BALANANDAN (Mukundapuram) : Sir, I rise to oppose this Bill. It is mentioned in the statement of objects and reasons that the Government has felt that the present law is not sufficient to deal with the increasing acts of vandalism and damage of public property. Therefore, this new Bill is being brought in. Therefore, the Government themselves are admitting that the present law enforcement machinery would not keep up law and order in the country. According to him, our present law is not sufficient to meet the situation. Therefore, the Home Minister is now coming to give more strength to the law enforcement authority. But, Sir, this claim has to be scrutinised a little more. He says, today we could not do it because the present day law is not sufficient to meet the situation, Acts of vendalism and damnge to public property could not be arrested in the present law and therefore a new law is being brought in. If you pass this, this is the law which is going to affect the en tire country except Jammu & Kashmir. Therefore, we must see that if the present law is properly implemented, we can arrest this kind of vandalism and damage to pubilc property. Therefore, this aspect and the scope of this Bill has to be examined and scrutinised a little more in the context of the situation prevailing today.

We have discussed in this House the situation in Assam. Somebody thought it fit that they would decide who should live in Assam and who should not and which property should be protected and which were not to be protected. The entire law enforcement machinery had completely failed in Assam. I will come to that question next.

Coming to Punjab, the present-day problem, some communalists think and decide everything there. They go round the cities and villages with sten guns and automatic weapons and name the people who are to be killed. Therefore, they decide who should live in Punjab and who should not live in Punjab. The situation went out of control, and the Government failed to do something effective. Still that situation continues there.

Now, I come to the State of Kerala. About Punjab, we talk of communalism. The ruling party claims to be against communalism. They are always saying so. I do not want to disbelieve that. But in Kerala, I find something else. There is a combination of communal parties in power along with the Congress Party. Here, the R.S.S. think and decide who should live in Kerala. Within a short period of time, 43 communists and sympathisers were killed, not in clashes, but while they were sleeping or they were walking. Some people cut off their heads. This is the situation in Kerala. The law and order machinery in the State completely failed.

As you have said, in Section 425 of the IPC the definition of the word "mischief" is given. It is not only protecting the property but also protecting the human beings. But the human beings are not being protected. It is not because of the insufficiency of the powers under the present law. But the law and order machinery of the State is not using the powers given under various Sections of the IPC which provide for punishment for various offences committed ranging from five years to ten years imprisonment. The people should feel that the Government can act if they want to act as per the law of the land. The Government should not budge an inch from that. The Government must not say that they are not able to maintain the law and order because the present-day

[Shri E. Balanandan]

law is insufficient and the fact is it is not being properly enforced.

Coming to Delhi itself, two or three days back the Home Minister said that in Delhi the crime rate is coming down, but the tendency is still on the rise. I do not know what it means. If we go into the figures of crime, we will find that in Delhi all types of crimes are on the increase. I want to quote some figures. I am quoting from the *Indian Express*. Take, for example, robberies. There is an increase of 26 per cent in the crime of robberies. In the first two months of this year, the number of robberies. were 33 and, during the corresponding two months of the last year, the number of robberies were 25. In the case of dacoities; the number was 5 this year and 3 last year; about murders, it was 38 this year and 29 last year; as for riots, it was 31 this year and 29 last year. So, when the Home Minister said that the tendency of crime was still on the rise, I agree that the tendency is on the rise.

This is the situation. The Government has got all the powers under the various Sections of the IPC to take steps to curb the crimes. But the law and order machinery in the States is not able to protect the property and the lives of the people as is expected from the Government. Some administrative competence, some kind of a principles stand on all these questions should be there. My friend was saying that there must be a common standard. It is correct. Look see the Congress-I Party. I do not wish to go deep into the political side. But still I have to give a small example.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : You are at liberty to say anything.

SHRI E. BALANANDAN : Don't take it the other way round. Since you are there, I have to be polite.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I will not take it that way.

SHRI E. BALANANDAN ; You are polite. My point is that the Chief Minister from Kashmir visited West Bengal recently in January, The Congress-I party did not like it. That also I can understand. They thought it fit to manhandle him. That also sometimes happens. Then the police have arrested some of these people who had misbehaved. Then what happened ? Immediately a faction led by the Congress-I, burnt five buses. For what ?

(*Interruptions*)

Is this the way of protecting public property. Perhaps, I do not know.

In 1981, there was some commotion in West Bengal. Congress-I Party organised a bandh. What happened then ? Petrol bombs were thrown in trams; buses etc. and the net result was, eleven people died including pregnant women and nurses.

This is the type of political attitude. Can a political party which condoms this kind of action, this killing of women by throwing petrol bombs, come and say we have to protect public property ? I am very glad that they are coming to protect public and private party. I am one with you. The question is we, as Communists, what is our position ? We are being attacked in Assam saying that we are against extremists. So, our heads are cut off. We are attacked in Punjab saying...

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : We are attacked.

SHRI E. BALANANDAN : In Puujab also, we are being attacked. Our students and our workers are attacked, For what ? We are opposing this kind of extremist activity.

In Kerala too, we are being killed and the Home Minister in Kerala is supposed to be a big man in talks, but he is protecting all these fellows who are killing us, when I am sleeping with my family at home, am I to be attacked ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : In Kerala, we do not come into the picture.

SHRI E. BALANANDAN : I welcome your statement.

(*Interruptions*)

श्री सत्य नारायण जटिया : जो हैं नहीं उनके बारे में नाम लेना आपका उपयुक्त नहीं हैं।

SHRI E. BALANANDAN : We are being killed. For what ? I can understand some clashes may come some day . Something may happen. I am not going to make it a political pawn.

In an organised way, they collect arms and go to homes in 50s and 60s and cut their heads and go away and the police is, not doing anything. They are not protecting anything. This is the way our country is now progressing, This has to be fought. If the Government comes forward for really fighting this kind of things, we are one with them. We do not want to damage any private or public property. Why should we ? It should not.

Today the required political will and administrative skill and administrative impartiality is lacking. To cover up that, this kind of a bill is being brought. However, if you are serious in this attempt, I hope you may succeed. I do not know. I am very apprehensive about the situation.

AN HON. MEMBER : You will cooperate.

SHRI E. BALANANDAN : I will cooperate for every reasonable thing on earth. It should be proper.

Coming to the bill itself, according to the definition of 'mischief', you need not commit any mistake. It is enough if you have the intention. In the Definition, Explanation (1) : If you have the intention, you can be brought to book. Therefore, this is so wide a clause that you can take any action against any body on the basis of this definition of 'mischief' in this Bill.

Somebody was saying that private property is excluded. No. It is there. It is there in proviso to (vi) of clause 2 (b) which reads like this :

> "Provided that the Central Government shall not specify any institution; concern or undertaking under this sub-clause unless such institution, concern or undertaking is financed wholly or substantially by funds provided directly or indirectly by the Central Government or by one or more State Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments."

Is there any concern, institution or undertaking on earth where public funds are not there directly or indirectly ? Every company is using funds directly or indirectly from banks or public institutions I do not oppose it. That is there. So nobody can say that private property is not included. So it is not only public property, the provisions really go beyond that. It includes private property too.

Another objectionable clause here is clause (5). Here if you want somebody to be bailed out, the prosecution should be given a chance to oppose. They must say 'No'. Therefore, that means that in some cases, if the Police wants to keep him there, he will be there. That kind of provisions I find in this clause. I do not know whether it infringes any of the fundamental rights.

Coming to Kerala experience—you say Kerala is the latest and Tamil Nadu also is the latest in this regard—what is the experience ? I have got a big list here and I do not want to read it out to you. There was an NGOs' strike. NGOs, as you know, are poor clerks and other small officials. They wanted

[Shri E Balanandan]

increase in wages and they went on a strike. This is the list of people arrested under the so-called Public Property Protection Ordinance. They did not damage any of your property but all these people, nearly hundreds of them, were arrested under this Ordinance. If you take it as a model from Kerala or Tamil Nadu and this enactment is going to be passed in this House and implemented in this fashion, what will be the position ? The position will be that rual culprits who are really damaging the property will go scotfree and workers and others who agitate for their democratic rights will be attacked. Is that the intention of the Government—you should make it plain.

Another point I would say. To-day double standards are there. Double standards means two kinds of approaches. When we, the workers, the poor workers, the teachers and college teachers go on an agitation, the Government comes down with a heavy hand, and we often find that the Government is very strong. But when people belonging to their classes, their kith and kin damage property, the government becomes weak. Even for some time the Government shut their eyes. This situation cannot continue for long.

With these words, I oppose this Bill.

SHRI B.K. NAIR (Quilon) : Mr. Chairman, Sir, I do not want to enter into any controversy. I only want to make a few suggestions. Now, my friend, Shri Balanandan had gone into certain aspects in regard to Kerala. Kerala is now governed by so many parties. Mr. Balanandan's party was in power—it was a coalition led by his party—at least three times in 1957, 1967 and in 1980. The last word he used was 'double standards'. Organised firings etc. can be applied even to his party also. At that time his party was in power. So many innocent people were killed in these days. How many were killed ? You must be able to find that out. How many strikes were suppressed, how many workers were beaten up and how many heads were broken—he will be able to find that out. What is happening in Bengal ? Any strike, be it the strike of electricity workers, the N.G.O.'s strike, all this is suppressed by violence. He talked about political violence In Kerala, at least the entire history of political violence starts with the Communist Party. I am here talking of the old period. The Congress of course believe in non-violence. Even if there is any upsurge, the philosophy of the Congress is non-violence—not violence. It was the leadership that came down heavily. Who started the political violence in Kerala ? The credit goes to the Communists Party. After their coming into power right from 1977, all the time, there were political murders. Now, they are complaining about the R.S.S. I will tell them that the R.S.S. are the sons of the C.P.M. The people who remained with CPM got disgusted with them and they thought that they had been suppressed and so they formed another party of violence. Who is murdering whom in Kerala ? All the parties in the CPM coalition are fighting among themselves. The CPM and CPI are killing each other. Killing is of course their monopoly—the monopoly of the Communist Marxists—and the R.S.S. only try to imitate them; let us not try to trade in these matters in the House. Violence has been there. One may say that this sort of phenomenon at times we may not be able to curb I know that machinery is not sufficient. We are trying to instil fear in the minds of the criminals that the punishment will be very severe. There are failures of law and order. What we are trying to do here is to prevent mob violence. The violence is on the rise. It is not the poor people who are involved—it is the leaders who instigate them. They burn the buses and throw stones on the police and run away and it is the poor people who get beaten. It is the leadership who should control them. When it comes to violence being resorted to we know how trains are sabotaged. In the days prior to 1977 when there was organised violence, trains were damaged and buses were

damaged. We have seen them. Let us not go into that. Let us not try to throw mud at each other. What I suggest is this. The organised violence in the form of agitation has become the fashion of the day. We have been seeing agitations like *rail rokho, road rokho* and all sorts of things. They put obstacles on the roads and they burn the trains and buses. This has become a common feature at all times. Let us not trade in these matters. Let us not try to gain a political each other. It is for us to set an example. Peace, cooperation etc. are ways of democracy. Let us tell the people.

In regard to this Bill, what I say is that it is the public property financed by Government which is being destroyed or damaged which we sought to be protected. I want to add this. There is a list here. Add also the property—indestructible property—given by Nature, that is, the forests, in this country which are being damaged. There is a wide scale destruction. Thousands of acres of forests have been destroyed; every day the organised gangs are marching into the forests and setting them to fire. Do we call it vandalism ? Let them not set it on fire, let them not cut the timber and take it away and then occupy the land. They destroy the timber of the forests, they take away timber and they encroach on the land. This also is an item of property. It has to be included io the items to be protected. That is our most inviolable assest. We cannot think of replacing this natural forest wealth. Other things we can replace but not this thing. They are not merely properties but they are for our protection; they safeguard our lives; they are making life livable in the earth, Even though it is not financed by the Government, let us try to prevent forest being destroyed indiscriminately. Such things are happening right from Kashmir to Kanya Kumari. No one would like the forest property to be destroyed in this manner. It is our public property number one, given by God, given by nature. We should include this property also for protection. As I said, other properties can be replaced but not this one. Therefore I request the Hon. Minister to include this as an item to be protected.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): सभापति महोदय, आज लोक संपत्ति नुक्सान निवारण विधेयक जो मंत्री महोदय ने पेश किया है, पेश करने के पूर्व आपने कहा कि इसका राज्य सभा में बहुत बड़ा स्वागत किया गया है। मान्यवर में अभी राज्य सभा की प्रोसीड़िग देख रहा था। मंत्री जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि इसका राज्य सभा में बहुत बड़ा स्वागत किया गया है। हो सकता है कि आपके पक्ष के दो चार लोगों ने इसका स्वागत किया हो, लेकिन आम राय यही रही है कि यह बिल जो पेश किया गया है यह जनतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध है। मान्यवर, इसमें मैं अपनी बात जोड़ते हुए कहूंगा कि हमारे यहां अध्यादेशों के जरिए विधेयक लाने की एक परंपरा बन गई है। यह देखा जाता है कि जब पार्लियामेंट का सेशन आने वाला होता है या 15 दिन; 20 दिन के बाद चलने वाला होता है तो एक अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। कभी मूल्य बढ़ा दिए जाते हैं। इस सदन की अवहेलना करके सत्ता पक्ष से इन दिनों जो काम किए जा रहे हैं, उनकी कोई मिसाल नहीं है।

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 20 जनवरी को यह अध्यादेश लाया गया, और 23 फरवरी से पार्लियामेंट चलने की घोषणा कर दी गई थी। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था या कौन सी प्रापर्टी देश की चली जा रही थी, कौन-सी ऐसी लूट हो गई थी जिसके लिए यह अध्यादेश लाना अत्यावश्यक हो गया था।

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

इस बिल को गौर से देखने से मैं समझता हूं कि इस बिल में कोई नई बात नहीं कही गई है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा। मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि 31-32 दिन के बाद जब यह बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया होता, अच्छे विद्वानों के जरिए सोच विचार कर पेश किया गया होता और समय देकर बहस कराई गई होती तो देश को एक दिशा मिलती। लोगों के मन में लोक संपत्ति के प्रति एक मोहब्बत नए ढंग से पैदा होती लेकिन ऐसा न करके लोक संपत्ति का केवल मजाक उड़ाया गया है।

मान्यवर, सीधे शब्दों में यह कहना उचित होगा कि देश की संसदीय परंपरा पर आप कब तक चोट पहुंचाते रहेंगे, इस तरह से बे समय विधेयक पेश करके कब तक जन जीवन को गुमराह कर कानून का मजाक उड़ाते रहेंगे। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अपनी लाइन क्लीयर करने के लिये एक कानून बनाने की आवश्यकता है कि यदि राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर देता है तो फिर सदन में उसे विधेयक के रूप में लाने की आवश्यकता ही न हो, और अपने आप इसको पास समझा जाय। ऐसा कर देने से सदन का समय भी बच जायगा और आप भी अपने मन की सरकार चलाते रहेंगे। कोई आलोचना का अवसर ही न रहेगा, किसी को कोई आब्जेक्शन करने का मौका ही न मिलेगा।

एक बात मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस बिल को लाने की आवश्यकता क्या थी ? मैंने इस बिल को पढ़ा है और देश के लोग भी पढ़ेंगे, इसमें कौन-सी नई बात जोड़ी है ? हां, एक, दो बातें हैं जिसका जिक्र बाद में करूंगा। आई०पी० सी० के सेक्शन्स 425, 430, 431, 432, 434, 435 में ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण इस बिल में सजा का प्रावधान करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने इस बिल में 6 महीने से ले कर 5 साल तक की सजा का वर्णन किया है। लेकिन आई०पी०सी० का सेक्शन 425 कहता है कि ऐसे कामों के जुर्म में 7 साल तक की सजा कर सकते हैं। इसलिये यह बिल बिल्कुल बेकार है, इसको लाना ही नहीं चाहिये था। आई०पी०सी० में मिसचिफ में पब्लिक प्रोपर्टी, गवर्नमेंट प्रोपर्टी और प्राइवेट प्रोपर्टी का वर्णन किया गया है। फिर इसकी क्या जरूरत थी। यदि इस बिल को पूरी तरह छानबीन कर के लाया गया होता और अच्छी बहस होती तो देश का लाभ होता।

आप कहेंगे आप तो विरोध कर रहे हैं, हम विरोधी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं इस बिल का कतई विरोधी नहीं हूं। लेकिन जिस ढंग से इसको पेश किया है वह गलत और बेबुनियाद आधार है। मैं इसका विरोधी हूं। देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहेगा सरकारी प्रोपर्टी को फना कर दिया जाय। सरकारी फैक्ट्री को लूट लिया जाय, बसों को आग लगा दी जाय, स्टेशन फूंक दिये जायें ? कोई भी सदस्य किसी पक्ष का हो, ऐसी किसी की मंशा नहीं है। हम चाहते हैं इस मुल्क में तिनके-तिनके प्रोपर्टी की, चाहे वह पब्लिक, गवर्नमेंट या प्राइवेट प्रोपर्टी हो, उसकी रक्षा होनी चाहिये। आज कलकत्ता, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र को जितना

नुक्सान हो रहा है वह सब को मालूम है। जैसा एक माननीय सदस्य ने बताया सबसे ज्यादा दोषी अगर कोई है तो कानून नहीं है बल्कि राजनीतिक है। मैंने देखा है बनारस में एक बस में आग लगा दी गई यू०पी० रोडवेज की, एक साल पहले। और इसलिये लगायी गई कि एक सत्ता पक्ष के व्यक्ति साइकिल से जा रहे थे, पीछे से बस चली गई और उसकी हवा लग गई और वह गिर पड़े। उन्हे कोई नुक्सान नहीं हुआ, न कोई जान ही गई।

उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और वह बेहोश हो गये। इसके बाद पीछे से उनके 10, 5 समर्थक आ रहे थे, बस पर ठेला पड़ा और उन्होंने कार से उसका पीछा किया। बस खड़ी कर ली गई। उस बस में से पेसेन्जर्स को उतारकर बस को फूंक दिया गया।

अब मैं 4 दिन पहले की घटना बताता हूं। शेरशाह सूरी यहां का शासक रहा है उसने बहुत से पुल और सड़कें बनवाई, मील के पत्थर लगवाये, सब कुछ किया है। जौनपुर, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, वहां पर उसने तीन पुल बनवाये जो कि आज उत्तर प्रदेश के गौरव माने जाते हैं। ये पुल इतने कीमती और मजबूत हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इत्तिफाक से पारसाल बाढ़ का पानी आया सई नदी में जलालपुर के पास से पुल के ऊपर से पानी बह गया। आपके इंजीनियर ने रिपोर्ट दे दी कि पुल गड़बड़ हो गया है, उस पुल को जन-भावना का आदर न करते हुए हटा देने की बात कर दी गई। आपके चीफ मिनिस्टर वहां जाते हैं, उनको हजारों पब्लिक घेर लेती है और कहती है कि इस पुल को हटवाइये मत। आपके लोग भी कहते थे और भी कहते थे लेकिन इंजीनियर रिपोर्ट देता है कि यह पुल इस परिस्थिति में है कि इसको समाप्त कर देना ही चाहिये, इसको हटाना चाहिये। वह इसलिये कहता है कि 5 लाख रुपया उसकी मरम्मत के लिये आ चुका है, वह कहां लगे। तो वह भ्रष्टाचार उस पुल को समाप्त कर रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह इस पुल के लिये जरूरी नहीं है कि पब्लिक प्रापर्टी को, गवर्नमेंट प्रापर्टी को ठीक करने के लिये यह पुल हटाया जाये। यह ठीक नहीं है। बल्कि गवर्नमेंट प्रापर्टी की सुरक्षा के लिये इसको तैयार रहना चाहिये।

ला एण्ड आर्डर की स्थिति मेरे मित्र ने बताई। इतनी बुरी परिस्थिति हो गई है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और असम को आपने देखा ही है न जाने वहां कितना-कितना पब्लिक प्रापर्टी को नुक्सान हो रहा है और कोई आदमी कुछ कर नहीं पाता है। कहीं छोटी सी घटना होती है तो आपकी पुलिस नहीं पहुंचती है। पता लगता है कि स्टेशन फूंक दिया गया। आप स्टेशन की रक्षा कैसे करेंगे? क्या आपका यह बिल रक्षा करेगा? वहां स्टेशन पर लाखों रुपये का नुक्सान हो जाता है, स्टेशन मास्टर मार डाला गया प्रापर्टी का बहुत नुक्सान हो गया।

पिछले 17 फरवरी की घटना है, मैं दिल्ली आ रहा था। एक मामूली सी बात हुई। बनारस कैंट में कांग्रेस (आई) के लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया कि मगध एक्सप्रेस रोकनी चाहिये—वाराणसी होकर चलनी चाहिये। हमने स्वागत किया कि मगध एक्सप्रेस इधर से चले और सोचा कि आपकी सरकार है 2 मिनट में मगध

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

एक्सप्रेस चलने लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और न कुछ किया गया और न आपको ही खबर लगी। वहां पर कांग्रेस (आई) के 100 गुंडों ने तिरंगा झंडा हाथ में लिया, इन्कलाब जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए वह स्टेशन पर रेल लाइन पर बैठ गये और बैठने के बाद उन्होंने सिगनल को उठा लिया। कांशी विश्वनाथ एक्सप्रेस आ रही थी, उन्होंने सिगनल उठा दिया और गाड़ी पर चढ़ गये। कुछ भाई इंजन पर चढ़ गये। ड्राइवर ने सीटी बजाई, कुछ लोगों ने उसको पीटना शुरू कर दिया। वाराणसी कैंट पर आपके आदमी थे, कांग्रेस आई के कुछ अच्छे लोग मौजूद थे, उन्हें खुद यह बहुत बुरा लगा, कहने लगे कि कमलापति त्रिपाठी को फोन करें, लेकिन वह सब नाटक था। उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर पब्लिक प्रापर्टी को नुक्सान पहुंचाया गया। कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ।

उसके बाद एक नाटक और हुआ है। कहा गया कि मुगलसराय से मगध एक्सप्रेस इधर से चलेगी। यानी, सब मामला ठीक हो गया। **(व्यवधान)** मै यह नहीं चाहता कि हम साफ कह कर इनको जलील कर दें कि ये डाकू हैं, इनकी पार्टी डाकू है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज-कल बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। इसमें सत्ता पक्ष का हाथ है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस): उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही से पता लगता है कि कौन डाकू है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: पिछले दिनों की घटना है कि श्री मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश विधान सभा की गाड़ी में जा रहे थे। गुंडों ने उसपर आक्रमण कर दिया। जब गाड़ी रुकी, तो उस पर गोलियां चलाई गई। गाड़ी में 11 सूराख हो गए और वह गाड़ी डैमेज कर दी गई। इन दोषी व्यक्तियों को कैसे सजा दी जाएगी ? क्या सरकार लालटेन ले कर खोज करेगी कि किस ने सरकारी गाड़ी को डैमेज किया ?

मैं समझता हूं कि यह बिल इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। हम सब को मिल कर विचार करना चाहिए कि इस बिल में कैसी, व्यवस्था की जाए, जिससे ला एण्ड आर्डर को मेनटेन किया जा सके। ला एंड आर्डर को मेनटेन किए बिना एक हजार बिल भी पब्लिक प्रापर्टी की सुरक्षा नहीं कर सकेंगे।

कारखानों में भी यही प्रक्रिया जारी है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में ऐसे इंजिन बनाए गए, जो तन्जानिया में फेल हो गए। इस कारण एक भी इंजिन नहीं बिका। क्या यह सरकारी प्रापर्टी का नुक्सान नहीं है ? इस कारण हम लोगों को दूसरों के सामने जलील होना पड़ता है। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। गृह मंत्री को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए।

अब मैं इस बिल के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं। क्लाज 3 इस प्रकार हैं :—

"3. लोक-संपत्ति को नुक्सान कारित करने वाली रिष्टि—(1) जो कोई उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की लोक-सम्पत्ति से भिन्न किसी लोक-सम्पत्ति की बाबत कोई कार्य कर के रिष्टि करेगा, वह कारावास

से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।"

यदि कोई व्यक्ति तीन लाख रुपए की बस फूंक देता है, उसपर सरकार क्या जुर्माना करेगी ? हमें विदेशों से सबक सीखना चाहिए, जहां पब्लिक प्रापर्टी को नुक्सान पहुंचाने वाले व्यक्ति का अंग-भंग कर दिया जाता है, उसको आजीवन-कारावास दिया जाता है या मृत्यु-दण्ड दिया जाता है।

आगे क्लाज 3 (2) (ङ) में कहा गया है :—

"·····कोई कार्य कर के रिष्टि करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डित किया जाएगा,"

जमानत के बारे में आपने विशेष उल्लेख किया है। आपने लिखा है :

"धारा 3 या धारा 4 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अभियुक्त या दोषसिद्ध कोई व्यक्ति, यदि अभि-रक्षा में हो, जमानत पर या अपने स्वयं के बन्धपत्र पर जब तक नहीं छोड़ा जायेगा जब तक अभियोजन पक्ष को ऐसे छोड़े जाने के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो।"

उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि कोई एक आदमी है जिसके बगल में एक सरकारी मकान है और उस मकान में किसी अन्य व्यक्ति ने आग लगा दी मान लीजिए हमारे चन्द्र पाल शैलानी जी जैसे व्यक्ति ने कह दिया कि शास्त्री जी ने आग लगादी तो मुझे पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया जायेगा और मुझे तब तक नहीं छोड़ा जायेगा जब तक कि शैलानी जी को मेरी जमानत का विरोध करने का मौका नहीं दे दिया जाता है या स्थानीय पुलिस को। मैं समझता हूं यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। फिर तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ही आप मुकदमा चला सकते हैं और इस प्रावधान की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। इसमें तो जिस किसी को पकड़ना होगा उसको किसी के इशारे पर पुलिस पकड़ लेगी। मैं तो यह समझता हूं कि सत्ता पक्ष विरोध पक्ष के लोगों को लम्बी अवधि तक के लिए जेल में रखने के लिए इस बिल का इस्तेमाल कर सकेगा।

और भी बहुत सी बातें हैं जिनको समय की कमी की वजह से मैं यहां पर कहना नहीं चाहता लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इस बिल में बहुत अधिक संशोधन करने की आवश्यकता है इस लिए अच्छा होगा कि इस बिल को स्थगित रखा जाए या सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए। अच्छा तो यही होगा कि इसको आप अभी विद्ड्रा कर लें और अगले सत्र में सुधरे हुए रूप में यहां पर लायें। यदि सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति से बचाया जा सके तो उससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस बिल को अगले सत्र में सुधरे हुए रूप में यहां पर पेश करें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण विधेयक का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

हुआ हुं शास्त्री जी ने अभी यह बात रखी कि कौन सी विशेष बात के लिए यह बिल प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हुं विशेष बात यही है कि इस बिल में प्राइवेट प्रापर्टी और पब्लिक प्रापर्टी को डिफरन-शिएट किया गया है और यह विधेयक पब्लिक प्रापर्टी के सम्बन्ध में है। आज पब्लिक प्रापर्टी का जिस प्रकार से विध्वंस किया जा रहा है, जिस प्रकार से उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको रोकने के लिए आवश्यक है कि डेटेरेन्ट पनिशमेन्ट की व्यवस्था की जाए ताकि इस प्रकार की असामाजिक कार्यवाहियों को रोका जा सके। इसी उद्देश्य को लेकर यह बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है और इसका मैं स्वागत करता हूं। जो भी सार्वजनिक सम्पत्ति है वह राष्ट्र की सम्पत्ति है और उसकी रक्षा करने का हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि यदि हमारी व्यक्तिगत सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है तो हमें कितनी पीड़ा होती है।

लेकिन राष्ट्र की सम्पत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो हमारा दृष्टिकोण एक अलग-सा हो जाता है। इस दृष्टिकोण मे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें राष्ट्र की सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति समझना चाहिए। राष्ट्र का निर्माण करना कितना कठिन काम है। कितनी मेहनत करके हम रेलवे स्टेशन्स बनाते हैं, कितनी मेहनत करके हम पुल बनाते हैं और कितनी मेहनत करके हम स्कूल भवनों का निर्माण करते हैं। उन साधनों को यदि एक दम से विध्वंस कर दिया जाता है। एक दम से तोड़फोड़ दिया जाता है उनको जला दिया जाता है कारण यह कि इस देश में ऐसे तत्व घुस गए हैं, ऐसी पार्टियां हैं, जो इन्सानों को प्रोत्साहित करती हैं।

श्री मूलचन्द डागा पाली : वे ऐसी कौन सी पार्टियां हैं ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : इस संबंध में मैं नहीं जाना चाहूंगा। कोई भी पार्टी यदि हिंसा को प्रोत्साहित करती है और कोई भी व्यक्ति यदि हिंसा को प्रोत्साहित करता है, तो वह कानून की दृष्टि से दोषी है। यदि कोई सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, वह दोषी है और कानून में कोई भेद नहीं हैं। राजनीतिज्ञों का कोई विशेष प्रावधान हो और आम जनता के लिए अलग प्रावधान हो ऐसा कानून के अन्दर नहीं होता है। इसलिए यह आवश्यक और जरूरी है कि हम यह कोशिश करें कि सार्वजनिक सम्पत्ति की तोड़फोड़ न हो। और इस प्रकार से नुकसान न हो और विनाश न हो। इसके लिए कानून में डिटरेंट पनिशमेंट का प्रावधान किया गया हैं। मैं चाहता हूं कि जहां छः महीने का प्रावधान किया गया है, उसको कम से कम एक साल तक बढ़ाया जाना चाहिए। जहां एक साल का प्रोवीजन किया गया है, क्लाज-4 में, उसको तीन साल तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। कहने का मेरा अर्थ यह है कि जो आग लगा कर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के जरिए नुक्सान पहुंचाता है, उसको कम.से-कम तीन साल की सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार आग जलाने से सार्वजनिक सम्पत्ति का काफी नुकसान होता है। इसके साथ-साथ यदि भवन में कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इसके लिए प्रावधान 436 है। इस प्रकार प्रापर्टी के साथ

मनुष्यों की क्षति हो जाती है। इसलिए इस कानुन में तीन साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। क्लाज-5 में कहा गया है—

> 'No person accused or convicted of an offence punishable under section 3 or section 4 shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless the prosecution has been given an opportunity to oppose the application for such release.'

इसलिए प्रोसीक्यूशन उसी दिन उपस्थित होना चाहिए। प्रोसीक्यूशन दो-चार-दस दिन का टाइम ले लेता है और उसको कस्टोडी में रखना अनुचित है। इसलिए ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि प्रोसीक्यूशन में एक दिन की भी ढील नहीं करनी चाहिए। 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर अपना केस प्लीड करने के लिए आ जाए। कानून में इस प्रकार का प्रावधान उसको कस्टोडी में रखना और इम्प्रीजनमेंट करके रखना उचित नहीं होगा। दूसरे इसको नान-बेलेबल आफेंस कर दिया जाए। नान-बेलेबल आफेंस पर भी बेल हो जाती है। बल्कि इसको काग्निजिबेल आफेंस कर देना चाहिए ओर इसको एस०एच०ओ० के जरिए इन्वैस्टीगेट किया जाना चाहिए, बहुत से केसेज हैड कॉस्टेबिल के जरिए इन्वैस्टिगेट करने के अधिकार में होते हैं।

एस०एच०ओ० से कम रैंक के अधिकारियों को इन्वेस्टीगेशन का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए इस सम्बन्ध में जो सजेशन्ज मैंने प्रस्तुत की हैं, उनके बारे में मन्त्री महोदय विचार करें।

यह जो कानून हमने बनाया है यह प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए बनाया है। प्रजातन्त्र में किसी के अधिकार को हनन करने के लिए नहीं बनाया है। जो भी इस प्रकार के तत्व हैं, गुण्डे हैं या कोई भी नौजवान जो हिंसा को भड़काता है, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है—उनका पूरी ताकत से विरोध करना चाहिए। जो भी हड़ताल करते हैं, बन्द करते हैं उनके नेताओं की यह जिम्मेदारी है कि उस हड़ताल में या बन्द में हिंसा की घटनाएं न होने दें। यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनका नेतृत्व असफल है। महात्मा गांधी जब कोई आन्दोलन करते थे, सत्याग्रह करते थे, उसमें यदि कहीं भी हिंसा की घटना हो जाती थी तो वे उस सत्याग्रह को बन्द कर देते थे। लेकिन आज स्थिति बिलकुल इसके विपरीत है। बंगाल में जो सरकार है, वह खुद बन्द घोषित कर देती है--यह कितनी अजीब बात है। दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां राज्य सरकार खुद अपने आप बन्द करती है....

SHRI AMAL DATTA (Diamond Harbour) : On a point of order. There is no relevancy in what the Hon. Member is saying. Kindly do not allow all this to go on record.

श्री सत्यनारायण जटिया : इससे पहले भी कुछ बातें कही गई हैं जो विषय से सम्बन्धित नहीं हैं, उनको भी निकाला जाना चाहिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): जैन साहब यह भूल गए कि तमिलनाडू के चीफ मिनिस्टर भी चावल ब पानी के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे।

MR. CHRIMAN : I have been there for some time. I still want to know whether to talk of relevancy is neces-

sary in Parliament. So, no point of order.

श्री वृद्धि चन्द जैन : मैं यही निवेदन कर रहा था कि कोई पार्टी यदि कोई आन्दोलन करे, कोई सत्याग्रह करे, बंद कराये, तो महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के अनुरूप कराये, अहिंसा के आधार पर कराये। कांग्रेस पार्टी भी यदि कहीं पर हिंसा का प्रयोग करती है तो उस को भी मैं ठीक नहीं मानता हूं। जो सिद्धान्त है, वह सब के लिए लागू होगा। वह सिद्धान्त ऐसा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के लिए लागू नहीं होगा और दूसरी पार्टियों के लिए लागू होगा, वह सभी के लिए लागू होगा कानून की व्यवस्था सब के लिए समान रूप से लागू होती है। इसलिए मेरा कहना है—आज यदि कोई भी पार्टी....

SHRI AMAL DATTA : Are you applying it or only saying it ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : हम इस के कार्यन्वियन का पूर्ण प्रयोग कर रहे हैं। हम तो महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चल कर पूर्ण रूप से उन का पालन कर रहे हैं। जब यहां जनता पार्टी का राज्य था तब भी हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा अन्य नेताओं ने जो विरोध किया वह कंस्ट्रीकिटव था। हम ने कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया।

....(व्यवधान)....

हम ने हमेशा अहिंसा का सिद्धान्त अपनाया, महात्मा गांधी का सिद्धान्त अपनाया।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र को अगर मजबूत करना है, तो हमें कुछ सिद्धान्तों का पालन करना पड़ेगा और अगर कोई भी अपने अधिकारों का प्रयोग हिंसात्मक तरीके से करेगा, तो वह प्रयोग भी प्रजातान्त्रिक तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri) : Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Resolution moved by my learned colleague. At the same time I oppose the measure which has been brought in this House though I support the spirit behind that particular measure. This Ordinance was issued on 28th of January, 1984 and it is on this basis that this measure has been brought. In my opinion, this measure which has been brought is incomplete and not only incomplete but, I am afraid it will create more confusion in the minds of the judicial officers, advocates and litigants. People may not know, even the police, as to whether a particuiar accused who has indulged in these activities, should be prosecuted under the ordinary law of the Indian Penal Code or whether he should be prosecuted under this particular measure in spite of the fact that there is a saving clause introduced in this particular measure. The Ordinance mentions that circumstances exist which render it necessary for the President to take immediate action. This has been copied down from Article 123 of the Constitution which is the job of the persons who draft these Ordinances and Bills not knowing whether in fact such circumstances do exist. The President has passed this Ordinance exercising his powers under Article 123. This is an analogous provision to Article 42 of the Act of 1935 the only distinction being that under the Act of 1935, only the satisfaction of the Governor General was sufficient but now the satisfaction of the entire Cabinet is necessary before the Cabinet advises the President and it is only on the satisfaction of the Government the President issues these Ordinances. So, I believe, not only the persons who drafted this Bill but the entire Cabinet applied its mind and has advised the President.

I would like to know as to what are those circumstances which compelled the Government to advise the President to issue this Ordinance ? I tried to go through the Explanatory Note and the intention is very clear—to arrest the political workers who are in the opposition of the ruling party in certain acts, in taking processions, in staging *dharnas*. I would like to quote four sentences from the Explanatory Note. In para 3 it says :

> "Public property, particularly buses, railways, government buildings, etc. are the main target of attack during *bandhs* or other agitations and to curb such acts this Ordinance and this Bill is being introduced."

You want to curb the agitations and you want to curb the bandhs, that seems to be the clear intention from the Explanatory Note. Not a single instance has been quoted as to why the Government was compelled to initiate this type of legislation. So, may I ask the Hon. Home Minister as to how many cases were filed before the day when the ordinance was issued, under the ordinary law ?

How many prosecutions were filed, in how many cases you have got convictions and in how many cases you found that the punishment that was given was not adequate, because of which you felt the necessity of bringing this legislation ? If on that particular day, namely, 28th or 29th January, you felt the need to bring this particular Ordinance, can you give a solitary instance from the 29th January up to this day where, under this Ordinance, you filed any case ? If not a single case has been filed from the date of issue of the Ordinance till today, it belies the intention which the Hon. Minister has repeatedly been saying in the other House and in this House, that circumstances did exist, because of which you advised the President to issue this particular Ordinance. I have tried to get some information, and I was informed that under this particular Ordinance no case came to be filed. If no case was filed and you did not find any case which was not adequately punished, then I would like to know initially as to why this particular Ordinance came to be passed. Therefore, I condemn this particular practice of the Government to issue Ordinance on the eve of the Parliament session, and I would like to have an answer on this particular point from the Hon. Minister.

With this prelude, I would like to make my observations about this particular Bill, and I assure you that I will restrict myself to the provisions of this particular Bill. It is said that this Bill has to be introduced to punish those who indulge in activities of arson against public property. Are we to take it that there is no provision in the Indian Penal Code, which makes adequate provision for adequate punishment, which we have now prescribed ? If I may bring it to the notice of the Hon. Minister—in fact, he knows it, and I know that—mischief by fire is punished with ten years of imprisonment under section 436.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : We want the minimum punishment to be prescribed.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: I am coming to minimum punishment. If you, in your wisdom, have brought this legislation only for prescribed the minimum punishment, then I would suggest that you could have added a proviso to section 435 that in case any public property is damaged or destroyed, the minimum punishment shall be six months and all this exercise of issuing the Ordinance and bringing a legislation later was absolutely not necessary. I feel that when the Hon. Minister made the suggestion, he was not serious about it. In fact, this legislation has been brought, as I have already said, for some other purpose, in connection with morchas and bandhs, which you have highlighted in your explanation. No other immediate reason or immediate cause has been given by you in your explanatory note, in your speech in the

[Shri Bapusaheb Parulekar]

other House and in this House or in the Statement of Objects and Reasons attached to this Bill.

Apart from that, under the Indian Penal Code the punishment is 5 years, 7 years and 10 years. Here the punishment that is provided for private property is 5 years and for public property 10 years. May I point out to the Hon. Minister that if the house of a private individual is gutted to fire because of the act of arson, under section 436, if the offence is proved, he shall be punished with ten years of rigorous imprisonment. But, under this Act, he can be punished only with five years of rigorous imprisonment. Therefore, this would confuse the mind of the judges and advocates. Clause 3(1) of the Bill says :

> "Whoever commits mischief by doing any act in respect of any public property, other than public property of the nature referred to in sub-section (2), shall be punished with imprisonment for a team which may extend to five years and with fine."

So, you say that for act of arson against public property the punishment will be 10 years and against private property 5 years. But, under the Indian Penal Code, acts of arson are punishable with imprisonment upto 7 years, 10 years and 5 years vis-a-vis private property.

Suppose my house is gutted to fire, if some mischief-makers have done it and I want to prosecute them, if I went under section 436, an intelligent lawyer on behalf of the accused may say this prosecution is not tenable in spite of the saving, you have to prosecute him under this particular clause. So, you are not making this provision deterrent, but you are making the punishment more lenient; it seems that the intention of Government is that if the property of a private individual is set on fire by certain people, then he should be punished for 5 years. Taking into consideration the political differences, if a man belonging to one particular party sets on fire the house of a person belonging to another party, he will not get a punishment of 7 or 10 years under the ordinary law, but be will get only a punishment of 5 years under this law.

Is that the intention of the Government ? I am requesting the Hon. Minister to explain this particular anomaly and this particular contradiction. Now, assume for a moment, as you have said it is not less than six months, a motor vehicle of a Police department is a public property. To puncture a tyre is a mischief under the Law. So, for puncturing the tyre, you want the man to be punished for ten years and in any case not less than six months. Is that your intention ? How you given a thought to it ? Those who have drafted this Bill either did not have time enough to draft it or they were told to hurry up with the Legislation and not to think of the pros and cons of it. Suppose we organise a Morcha and we come before the Parliament. And in that melee the gate of the Parliament is damaged because of the huge amount of the crowd. So, in that case punishment is ten years because of the mischief committed to the Parliament property. And if a small stone is pelted on the public property, there too punishment is ten years.

You may say we have given the discretion to the Magistrates to give the punishment upto six months. But don't you think Mr. Minister that pelting a stone at the gate, which amounts to be a mischief—and you yourself are a lawyer—whether it is correct that he should be sent for a period of six months ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : The lawyer will come to my rescue. I am not a lawyer.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR; Mr. Chairman, these are the anomalies and it is absolutely necessary to give a thought to them. I suggest before you draft, it is better that you take the

advice of some advocates, if not from this side, at least from that side, so that these anomalies may not occur.

With this I would like to make a few suggestions as far as this Bill is concerned. Sir, I entirely agree with my friends that we have no dearth of laws. What we lack is the political will to implement the laws, which are already in existence. In this connection if you really want to make the provisions deterrent, why don't you amend the definition of the word 'mischief'? Why don't you say as it is in the Penal Code, and don't ask the prosecution to prove these things. I quote the definition :

> "Whoever is intent to cause or intent that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public property or if any person causes the destruction."

Why not say : "Whoever causes destruction on the public property". Why you want to know whether he had the intention to cause wrongful loss? On these basis many a time accused are acquittad. Now, if a person goes and sets fire to a building or a train, it is necessary for the prosecution to prove that it was his intention? Or whether he knew that wrongful gain would be caused to him? If really it is your intention to make this law more deterrent and if, in fact, you want to have a check regarding these incidents, I would request you to delete this Clause and retain "Whoever destroys". That is sufficient.

Now, coming to the definition of the public property, really I am at a loss what exactly does the Government mean. In Clause 2, you have defined public property so as to include Central Government property, local Government property and State Government property etc. Now, while making the Clause penal, you have said :

> "Whoever commits mischief by doing any act in respect of any public property,"

In that (a), (b), (c), (d) and (e) you have not included the Central Government property, you have not included the State Government property. Tnat is to say, if tomorrow some act of arson is committed with regard to the building of the Parliament, this Clause 3 will not be applicable. So, you make the definition such as to include all properties of the Centre and State Government. While making the offence of arson vis-a-vis the public property penal, you only selected a few items such as :

> "(a) any buliding, installation, or other property used in connection with the production, distribution or supply of water, light, power or energy;" oil installations, sewage works, mine or factory and any means of public transport and telecommunication.

So, public undertakings is excluded Parliament is excluded, the State Legislatures are excluded, Secretariats are excluded. Every other thing is excluded.

I may also request one more thing that now the offences of arson are on the increase against the religious institutions. We are finding that in Punjab, gurudwaras are gutted, they are set on fire, temples are set on fire. Don't you think that these properties of the trusts also should be treated for the purpose of the offence of mischief and public property? You are not doing that. Somebody has given some direction saying that 'we want to protect the public porperty and the publie property is only oil installations and some street lights and some railways' and all that. Give a serious thought to it. If, in fact, you want to achieve the result, I respectfully submit that this is a haphazard way, totally incomplete legislation, and it needs a lot of changes if you want to achieve results and avoid confusion.

Sir, I want to add one more thing, and I would request the Hon. Minister to consider the suggestion which I have been repeatedly making. Of course, my lawyer friends do not agree with me because that is against the interest of

[Shri Bapusaheb Parulekar]

the lawyers as a class. But speaking as a citizen I have made this suggestion in this House, but no proper attention has been given to it, and I would like to make this suggestion taking this opportunity. As I have said, there has been no dearth of laws. There are so many laws. But in spite of these laws and bringing so many legislations, and converting our Parliament into a mint of legislations, we are not achieving the objective. The reason is that you are not bringing the necessary legislation and you are indulging in unnecessary lgislation. It is absolutely necessary to amend the Criminal Procedure Code if you want to achieve the results. And it is my saying and it is my experience in the bar, if I may say, that if we introduce the European jurisprudence in our country, we will get the results which we want and the phenomenon of 90 per cent acquittals will disappear. It is high time now to reconsider as to what jurisprudence we should have in our country.

16.42 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*].

Mr. Chairman, in our country, the accused has to keep quiet till the end. He is not supposed to open his lips. He sits tight-lipped. In cases of rape prosecution does not know whether the defence of the accused is on consent or is on alibi. So the prosecution has to bring all that evidence. In cases of murder, whether it alibi or whether it is self-defence, he does not know. In case of mischief also, it does not mean that the prosecution does not come in the case of alibi or in the case of self-defence and all that. Therefore, I suggest that the Criminal Procedure Code should be amended in right earnest so as to include two things on the basis of the European jurisprudence and the Criminal Procedure Code which is now in vogue in France that no sooner the charge-sheet or the charge is framed against the accused than the accused shall be called upon to give his defence whether he is going to plead alibi or whether he is going to plead self-defence. So, that will restrict the scope of litigation, that would restrict the time that is consumed in courts and that would avoid the delays in these cases.

The second thing which is absolutely necessary is that the cross-examination of the accused should be a must. In our laws we say that if the accused so desires, he may enter the witness box, but if he does not enter the witness box, adverse inference shall not be drawn. And if you put the accused to the test of cross-examination, I feel that 90 per cent justice will be done. Today he has to keep quiet, he only says, 'This is not true, this is not true, this is not true.' So, on these lines when you make the amendments on some other suggestions which are repeated here—because the time is very short, I will not repeat them but—it is necessary to give a thought to the amendment of the Criminal Procedure Code which would curtail the time and which would give justice to the complainants also. Now, in these days what we feel is, only justice is to be done to the accused and there is no justice to be done to the complainant. This aspect we have to take into consideration and if you want to achieve the results by amending the Penal Code and by making the Act more stringent, no purpose is going to be served. It is absolutely necessary to change the entire system of laws. Then alone the object will be achieved.

With these words, I submit that the Government has brought in a haphazard way this particular legislation, it is incomplete, it is confusing. Therefore, you better withdraw this Bill and hence forward, kindly don't bring ordinances on the eve of the Meeting of this Parliament. That is all.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, सब से पहले हमें यह जानना चाहिए कि आदमी के क्रुद्ध होने का कारण क्या है, वह क्यों भभक उठता है। एक कारण तो यह है कि जब लोग समझते हैं कि सरकार उनकी आवाज को नहीं सुनती

है, तो वे क्रुद्ध हो उठते हैं। इस लिए जब कभी कोई आन्दोलन हो, तो सरकार को प्रिवेंटिव मेजर्ज लेनें चाहिएं और उन लोगों को बुला कर उनकी बात को सुनना चाहिए।

लेकिन इस बिल की मंशा क्या है? मैं समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाने की एटेम्प्ट भी करता है, उसे देखते ही गोली से मार देना चाहिए। अगर इस बिल में मेरा प्राविजन होता, तो मैं समझता कि सरकार कोई ठोस मेजर्ज ले रही है। आधे मन से किए इस काम से कोई फायदा नहीं होगा।

हम देखते हैं कि स्टुडेंट्स बड़ी-बड़ी बसों को जलाते हैं। ऐसा लगता है कि सरकारें भी इस प्रकार की भाषा को जल्दी समझती हैं। जब लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो वे अपनी भावनाओं को इस तरह की विनाशकारी कार्यवाहियों से प्रकट करते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का यह तरीका अच्छा नहीं है। आईoपीoसीo में मिसचीफ की परिभाषा दी हुई है। अगर कोई जान-बूझ कर राष्ट्र की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे देखते ही गोली मार देनी चाहिए। अगर यह कानून बनाया जाता कि राष्ट्र की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का जिसका इरादा भी होगा, उसे उसी समय गोली से मार दिया जाएगा, तो यह एक नई बात होती जो व्यक्ति अपना क्रोध राष्ट्र की सम्पत्ति को नष्ट करके प्रकट करता है, वह देश का दुश्मन है।

इस बिल को लाने का मकसद क्या है? इस बिल का हैडिंग है 'प्रिवेन्शन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी'। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि जो पब्लिक प्रापर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, उसे सजा दी जाएगी। लेकिन प्रिवेन्टिव मैथड क्या है? सरकार कहती है कि कड़ी सजा देने से लोगों को शिक्षा मिलेगी। यह प्रिवेन्शन नहीं है। प्रिवेन्शन का मतलब यह है कि नुकसान करने से पहले ही उसको रोका जाए।

इसलिए इस बिल को लाने के पीछे जो आपकी इच्छा है और जो आपका इरादा है उसकी पूर्ति होती है या नहीं —यह देखना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें जो ट्रायल होगा वह कैसे होगा? आया समरी ट्रायल होगा या वारन्ट केस के आधार पर ट्रायल होगा। यदि वारन्ट केस की तरह से ट्रायल होगा तो जो आपका पर्पज है उसकी पूर्ति नहीं होगी वारन्ट केस का तो मतलब यह होगा कि कम से कम दो साल के बाद उसको सजा मिल सकेगी। इसलिए आपको कोई प्रोसीजर ले डाउन करना चाहिए कि किस तरह से ट्रायल होगा। यदि आप समरी ट्रायल रखें तो कोई पीरियड रख दीजिए कि उस पीरियड के अन्दर कोर्ट फैसला दे देगी। मैं तो समझता हूं आन दी स्पाट मौके पर ही सुनवाई करके कोर्ट फैसला दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन जिस प्रकार से आपने रखा है उससे तो आपका पर्पज सर्व नहीं होगा। मैं समझता हूं कुछ सख्ती होनी चाहिए। अगर कोई राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसको जल्द से जल्द सजा देने का प्रावधान होना चाहिए।

SHRI N. K. SHEJWALKAR (Gwalior) : Mr. Chairman, Sir, earlier I had no intention to say something about the Bill though there was a resolution in my name. I passed it on to m

[Shri N. K. Shejwalkar]

learned friend Mr. Satya Narayan Jatiya and so he moved the resolution. After hearing all the Hon. Members here, particularly Shri Parulekar who has given a very learned speech in respect of this legislation, I want to add something more to what he has said. He ha svery ably pointed out the anomaly of clause 3 and clause 2. The public property is being saved actually from the trouble, from the mischief which the present Bill is going to do. I only agree that this is a sort of hasty legislation which has been brought in. The purpose—I do not know whether—is served or not, I oppose to such ordinances because all the aspects of the ordinance cannot be considered unless it is brought in here in the form of a Bill. What happens? If you bring in an ordinance, you have to bring the Bill and you have to get it passed. Then, the mischief is already done and all the defects which are introuced in the ordinance are automatically followed here. I would, therefore, request the Hon. Minister and the Government again that before they bring in an ordinance they must think thrice.

Now, there are certain points which I want to make. For examle, whether there should be any law which may fix up minimum punishment ? The Hon. Member said, "I want to fix minimum punishment". Should there be any law to like this ? I feel there should not be any law which fixes any minimum punishment. What happens is, you are taking away the discretion of the court. The court is expected to give any punishment. When any limit of punishment is the provided, the court has to consider all the aspects. It is not that you just push the button on and automatically the punishment is there. It is not a computer. After all, it is a human mind which works and it has to be weighed on the basis of evidence and all that. Of course, the punishment may vary a little according to an individual judge. But ultimately we are thinking and talking of honest judges and of the whole procedure which is honest. Therefore, putting this sort of limit is not correct. You are disbelieving the court themselves. They may give more punishment or less punishment.

My hon. friend has pointed out an example that a stone is thrown and there is a little damage caused to the property and the punishment will be ranging from 1 year to 10 years. This sort of a clause should not be there in any legislation. You can provide deterrent punishment, no doubt. But you leave it to the court. Let the court decide about the quantum of punishment. Let the court see what is the nature of the offence committed and, on that basis, let the punishment be given.

Secondly, there is Clause 5 regarding bail. Why should you make a provision like this at all ? As a practising lawyer myself and others also know that no court grants bail unless the other party is heard. The purpose here is to hear the other party. Without hearing the other party, no bail is granted by the court. You should not use the word "oppose". Why should the prosecution oppose ? It becomes incumbent upon the prosecution to oppose. Prime facie, some case may be there and it may be found later on that of course it is not of a serious nature and that it is actually a doubtful case. Once a person is arrested, you say that the prosecution shall "oppose" the bail application. This is what is meant by it. That is not necessary. If at all, it could have been said that without hearing the prosecution, the bail should not be granted. It is normally not done. By way of an abandunt caution, you want to put that phrase also. The wording is :

> ".....unless the prosecution has been given an opportunity to oppose the application for such relese."

I am afraid, this provision is also not call for and such a clause should not be put in any legislation.

Basically, I put a question to you : How do you distinguish the nature of an offence when the subject—matter is property, whether it is public property or individual property. I may give you an example. We are in politics for long. Everyone gets a good fortune or an opportunity when the people gather opposite one's house and do some mischief. Now, my house was stoned at last three times. Unfortunately, some glass panes in my windows were broken. That is always a target for them. I have now changed the structure—I could not do anything else—and put a wire net. I do not want in anyway to accuse or bring in any party...(*Interruptions*) When I say, the District President of the Party who led a procession where I live, who else can it be ? Everybody knows who is in power there. I do not want to name anybody.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Enough has been said.

SHRI N. K. SHEJWALKAR : ऐसा कहा जाता है कि इशारा काफी है।

Anyway, what is the purpose of this provision ? How do you distinguish between a public property and a private property ? You can distinguish between a purpose. I agree with you what you are doing for the purpose. The purpose may be all right. For example, politically, with motivation, to just destroy somebody's property who belongs to another party may be ruling party or any other party, if the intention is to provide for punishment for that type of an offence, I will be with you. But how can you distinguish between a property ?

After all, there may be a bus or car. For example, what happened during Punjab roits or during riots in other places ? Some individual people's cars were obstructed and they were burnt. Don't you think it is a serious offence ? How can it be brought under this provision ? How do you want to check that ?

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : MPs' property should be included in the definition of "public-property".

SHRI N. K. SHEJWALKAR : I may not be an MP, I may be an office-bearer of the party. On that account, if some attack is arranged against that property, how can you stop that mischief ?

Ultimately, the democracy has to be purified. Unless you want to execute the law in the right way, whatever you make a provision, it will not be of any help. That apart, let us make a provision in such a way that it serves the purpose which you have in mind.

If you had the purpose which Shri Bapusaheb Parulekar has said that you just want only to do something against the Opposition, I never feel that Mr. Venkatasubbaiah being there will do.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : He may not be there. He has not opted for it.

SHRI N. K. SHEJWALKAR : It is a very serious thing. I want to bring these three points, particularly, not about property, but the purpose, should be clarified and there should not be any distinction between the property of A or B or C. After all, it is all public property. A car may be of an individual or of a mill property. That is differentiated. I do not know how it can work It is very difficult to work. If I go in a car which belongs to the Company, of course, the offence becomes serious. If I go in my own car, then the offence is not serious. What is the way out, I do not know.

You have to get the Bill passed. But still, think about these things.

Unfortunately, we have not moved amendments.

That is the whole difficulty. The whole purpose is that it is difficult to put amendment to this piece of legislation. The whole of it is very bad.

[Shri N. K. Shejwalker]

Every item of it is not correct, though the intention is correct.

With those words, I just submit, please reconsider at what stage and how. That is up to you. I leave it to you.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस विचार का हूं कि इस तरह का विधेयक बहुत पहले आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, देर-आयद-दुरुस्त-आयद। अगर कोई अच्छा काम विलम्ब से प्रारम्भ किया जाय, मैं फिर भी उसका स्वागत करूंगा। आजादी के बाद हमारे नेताओं ने, कर्णधारों ने, अपने देश में किस तरह की शासन व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर विचार किया और एक राय से देश में प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाई। जब देश में लोकतन्त्र की, प्रजातन्त्र की, स्थापना हुई तो इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को, सभी वर्गों को पूरी तरह से आजादी दी गई। हर आदमी को अपने विचार व्यक्त करने, हर आदमी को प्रदर्शन करने, हड़ताल करने और अपनी राय को प्रकट करने का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया। लेकिन इस अधिकार का कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया और आज भी किया जा रहा है। वे लोग कौन हैं, किस तरह के लोग हैं जो इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं—इसका एक साक्षात प्रमाण आज हरियाणा, पंजाब और असम में देखने को मिलता है। वैसे मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि जलसे न किए जायें, आन्दोलन न किए जायें, हड़ताल न की जाए या किसी यूनियन या संगठन को अपनी बात कहने का अधिकार न हो। उनको यह अधिकार होरा चाहिए, लेकिन वैधानिक तरीके से। क्या हम किसी पुल को उड़ा कर, रेलगाड़ी को आग लगा कर, बसों को जला कर, सरकारी इमारतों को बरबाद करके ही अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, अपनी इच्छा या अपनी मांग मनवा सकते हैं ? ऐसी बात नहीं है। अगर किसी भी पार्टी की या किसी भी संगठन की कोई जायज मांग है तो सरकार उस पर सहानुभूति और गम्भीरता से विचार करती है और उसको मानती भी है। इसीलिए मैंने कहा है कि यह बिल जो आज लाया गया है, बहुत पहले आना चाहिए था। अगर यह बिल पहले आ जाता तो मैं समझता हूं आज तक जो जो अरबों और खरबों रुपए की सम्पत्ति नष्ट की जा चुकी है, आन्दोलनों के द्वारा या दूसरे तरीकों से, विध्वंसक तरीकों से, शायद वह बरबाद न हो पाती और राष्ट्र का नुकसान न होता।

मेरे बहुत से विद्वान साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लोक सम्पत्ति को उन्होंने अपनी तरह से डिफाइन किया है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं—लोक-सम्पत्ति का मतलब है—सरकारी सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति का मतलब है—जनता की सम्पत्ति, जनता की सम्पत्ति का मतलब है—हमारी अपनी सम्पत्ति।

हम सरकारी सम्पत्ति का कोई नुकसान करते हैं, उसको जलाते हैं या तोड़-फोड़ करते हैं, तो इस तरह से अपना ही नुकसान करते हैं, जोकि मैं समझता हूं कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए

आदमी को बहुत ही ब्रौड-माइन्डेड होना चाहिए और उसके दिल में देश के प्रति मुहब्बत और देश-प्रेम की भावना होनी चाहिए।

यह देखने में आया है कि आज देश में सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है और इसको रोकना और इसको लगाम देना बहुत ही अनिवार्य है। अभी बहुत से मित्रों ने पंजाब हरियाणा और आसाम की मिसालें दी हैं। यह बात सही है कि पंजाब और हरियाणा में जहां एक ओर जानें गई हैं, वहां सरकारी सम्पत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ है। कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं बम छोड़े जा रहे हैं और कहीं सम्पत्ति को नष्ट किया जा रहा है। इस तरह की चीजें जो की जाती हैं, वे अपराधियों और जो असामाजिक तत्व घुस आए हैं उनके द्वारा की जाती हैं। कोई पार्टी आन्दोलन करती है या अपनी मांगें रखने के लिए कोई रैली करती है, तो उसमें अक्सर ऐसा होता है, मेरा यह लांक्षन नहीं है और मैं किसी पालीटिकल पार्टी या मजदूर यूनियनों के जो संगठन होते हैं, उनको कोई दोष नहीं देना चाहता, कि जो अपराधी तत्व होते हैं, जो पेशेवर अपराधी होते हैं, वे पेशेवर अपराधी और असामाजिक तत्व उन जलसों में आन्दोलनों में प्रवेश कर जाते हैं और फिर तोड़-फोड़ करते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि जो निर्दोष लोग हैं, उन पर भी इसका आरोप आ जाता है और इस तरह से लोक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है। जब लोक सम्पत्ति, जोकि राष्ट्र की सम्पत्ति है, उसका नुकसान होगा, उसको नष्ट किया जाएगा, तो वह एक तरह से जनता का ही नुकसान होता है नतीजा यह होता है कि जिस सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसको पुनः बनवाना पड़ताहै। ओवरा का पावर हाऊस जो जल गया था, उसको दोबारा बनवाया जा रहा है और उसमें करोड़ों रुपया लग रहा है। सार्वजनिक संपत्ति जो नष्ट होगी, तो उसको दोबारा बनवाना होगा और उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाए जाएंगे। इस तरह से जनता पर जो टैक्स लगेंगे, उनसे उसकी क्षति-पूर्ति की जाएगी। वैसे भी हम यह देखते हैं कि विभिन्न करों के रूप में सरकार जो पैसा जमा करती है, वह देश के निर्माण कार्यों में काम में आता है और ऐसे कामों में उसको लगाया जाता हैं, जोकि सरकारी होते हैं। किसी सरकारी चीज को नुकसान पहुंचेगा, या तोड़-फोड़ की जाएगी, तो उसकी क्षति-पूर्ति के लिए सरकार को नये-नये टैक्स लगाने पड़ेंगें। सरकार के पास कोई मशीन तो है नहीं या कोई ऐसा पेड़ नहीं है, जिस पर रुपये लगते हों, जिनसे उसकी क्षति-पूर्ति की जा सके। इसलिए स्वाभाविक है कि जनता से पैसा लिया जाएगा और उस काम को पूरा किया जाएगा क्योंकि सरकार का कोई काम रुकने वाला तो नहीं है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, उसमें जो सजा का प्रावधान है, वह बहुत कम है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि अरबों और करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है और यह नहीं सोचा जाता कि आखिर इसका अनजाम क्या निकलेगा। इसीलिए कड़ी-से-कड़ी सजा की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि इसके लिए किसी को गोली मार दी जाए। गोली मारने का

]श्री चन्द्र पाल शैलानी]

मतलब किसी की जान लेने से है। जान लेने से पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि इसका अपराध क्या है, इसका जुर्म क्या हैं और अगर जुर्म साबित हो जाता है, तो कोर्ट में उसके लिए मुकदमा चलना चाहिए। सजा देने का मतलब यह नहीं हैं कि उसको गोली मार दी जाए। उसको कड़ी सजा दी जाए लेकिन इसमें जो 6 महीने और 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है, मैं इसका विरोध करता हूं और मैं मन्त्री जी से माँग करता हूं कि इसमें अधिक से अधिक और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

इन शब्दों को कह कर मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस विधेयक का सही माइनों में पालन किया जाएगा, तो मेरा विश्वास है कि इससे राष्ट्रीयता की भावना लोगों में बढ़ेगी और हमारे लोकतंत्र और राष्ट्री एकता को बल मिलेगा। हमारे विरोधी दलों के लोगों को यह डर है कि इसका दुरुपयोग होगा। वे निश्चिन्त रहें। इससे उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर कोई नुकसान होगा, तो उसका होगा, जिसकी कारगुजारी हस तरह की होगी। बहरहाल हमारा मंशा किसी विरोधी दल के नेता, यूनियन के लीडर, मजदूर नेता को दंडित करने का नहीं है।

इस बिल का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हो और राष्ट्रीय सम्पत्ति को लोग नुकसान न पहुंचाएं।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: इस बिल का समर्थन करते हुए मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : कम्युनिस्ट हैं इसलिए ?

श्री विजय कुमार यादव : कम्युनिस्ट हूं इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि इसमें जिन बातों की चर्चा की गई है और जो उद्देश्य बताए गए हैं उससे सरकार की राजनीतिक मंशा स्पष्ट हो जाती है।

राष्ट्रीय संपत्ति के साथ चाहे कोई भी खिलवाड़ करता हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आपने अपने उद्देश्यों में बताया है "बन्द एवं अन्य आन्दोलनों के दौरान सरकारी संपत्तियों को क्षतिग्रस्त होने से रोकना।" इस सिलसिले में एक तो अपना उदाहरण पेश करूंगा और एक हमारे माननीय सदस्य हैं, उनके साथ जो घटना हुई, उसकी चर्चा करूंगा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब भी देश के अन्दर राजनीतिक उथल-पुथल शुरू होती है और कांग्रेस को खास तौर से सत्ता का भय होने लगता हैं तो इस तरह के कानून पेश करके सही दिशा में जाने वाले उन आन्दोलनों का दमन करने के उद्देश्य से इस तरह के कानून लाने का सिलसिला रहा है। 1965 में सभापति जी मुझे डीoआईoआरo में गिरफ्तार किया गया। इल्जाम यह लगाया गया कि मैं किसी पोल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और टेलीफोन का तार काट रहा था।

श्री एन० के० शेजवलकर : यह तो सबमें लिख देते हैं ।

Just for the information of the hon. Members. Mr. Trivedi, who was a member here, he was lame and he was charged with trying to take out the wires from the telephone pole.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : At a height of 40'.

SHRI N. K. SHEJWALKAR : And at the age of 65 foot.

सभापति जी, दूसरा उदाहरण पेश करता हूं श्री भोगेन्द्र झा जी हमारे माननीय सदस्य हैं जो एक पुराने स्वतन्त्रा सैनानी हैं। गाजियाबाद में मजदूरों का आन्दोलन हो रहा था। वहां वे गए। पुलिस ने जानबूझ कर अपनी जीप को डैमेज कर दिया और वहां के लोगों पर मुकदमा चलाया।

आज जब देश के अन्दर आर्थिक संकट है, सामाजिक संकट हैं, महंगाई बढ़ रही है तो उत्तरदायित्व का सवाल सरकार के सामने आता है। सभापति जी आपको मालूम होगा कि जब कभी भी मिल या फैक्ट्री के अन्दर जब मजदूरों की मांगें पूरी नही होती हैं ओर जब उनका आन्दोलन शुरू होता है तो मिल मालिक उस आन्दोको दबाने के लिए सरकारी मशीनरी को अपनी तरफ लाने के लिए मकानों में आग लगवा देता है। इंस्टालेशन को आग लगवा देता है। कहीं-कहीं एंटी सोशल एलीमेंटस के द्वारा पुलिस पर अटैक कराता हैं। उनके सामानों की तोड़-फोड़ करवाता है जिससे कि मजदूरों का आन्दोलन बदनाम हो और सरकार को दमन करने का मौका मिल जाए। इस तरह से कानून पहले भी बनाए गए हैं और जब कभी भी विरोधी पार्टी ने इसका विरोध किया तो ला एण्ड आर्डर की बात कही गई। 1980 के बाद कई बार इनका विरोध किया जा चुका है और हर बार सरकार की ओर से यह कहा गया कि इसका पोलीटिकल इस्तेमाल नहीं होगा। विरोधी पार्टी के दमन के रूप में इस कानून को नहीं लाया जाएगा।

लेकिन व्यवहार में खुद यहां के माननीय सदस्य श्री ए० के० राय गवाह हैं उनके खिलाफ उस कानून का इस्तेमाल किया गया, पूरे देश के खिलाफ इस्तेमाल किया गया इमरजेंसी के दौरान। इसजिए जिस एजेन्सी के जिम्मे इस कानून का इमप्लामेंटेशन सौंप रहे हैं, जिस तरह उससे आप काम लेते हैं और जो आपका स्टैण्डर्ड है और जिस तरह से आपकी पापुलैरिटी में गिरावट होती जा रही है, देश के अन्दर जो गहरा आर्थिक संकट हो रहा है, समस्याओं का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं एसी स्थिति में निश्चित तौर पर इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा, और किसान, मजदूर, विद्यार्थी, जनता और पीड़ित और शोषित लोग जब अपनी आवाय उठायेंगे, आप उनकी सही बातों की उपेक्षा करेंगे, और उनका दमन करने के लिए आप इस कानून का इस्तेसाल निश्चित करेंगे। क्योंकि इसके पीछे आपकी मंशा गलत है और इसका इजहार भी होता है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। जहां तक टैक्नीकल सवाल हैं उन पर हमारे और साथियों ने कहा है। मेरा विरोथ करने का सबसे बड़ा आधार यही है जो मैंने बताया।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

SHRI G. NARSIMHA REDDY (Adilabad) : Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Bill for the simple reason that from the days of our Independence, we have been seeing it. Our Hon. Minister who has introduced this Bill is very much experienced; he was in the public life and was a Member of Parliament from the very beginning. We have seen various types of *bandhs* and and so on. In any type of agitation or *bandh*, the first target is the public properties like the buses, railways etc. I am sure any hon. Member in this House or outside will have no objection to this Bill.

One of the hon. Member, I think, Mr. Parulekar, a very respected and very qualified advocate, has tried to mislead the House and the people here.

MR. CHAIRMAN : He is qualified.

SHRI G. NARSIMHA REDDY : He is qualified in doing that, I am saying that he is capable of doing it. I shall point out what he is doing. He had read from the explanatory note of the Bill. I shall read only three sentences from para 3. It is said therein:

> "The public property, broadly, the buses, railways, telephones, government buildings etc, are the main target of attack during riots, bandh or other agitation and, to curb such acts, it was considered necessary to undertake minimum legislation".

Here he is telling us that the object of the Government is to use legislation to curb the bandh and the agitation. If I have understood him wrongly, he may correct me. I would like to say that this is so simple. I am not a lawyer; nor am I a Ph.D. I know simple English. It is so clear here. During the agitation or during bandh or other agitations the main target of attack is on the public property. The word used here is 'to curb such act'. The act is 'destruction of the public property during bandh'. It is not curbing the bandh as such. It is the act done by the people during a *bandh* or during an agitation, I would like to know one thing from hon. Members opposite. Do you want the people who are engaged in agitations and bandhs to destroy public property ? You please tell us.

MR. CHAIRMAN : Mr. Reddy; as you know, in some States, the Governments themselves declare bandhs.

SHRI G. NARSIMHA REDDY : Sir, I take this opportunity to request the Hon. Minister to use his experience and see whether this legislation is sfficient at all to curb destruction of public property. If you total up all the destructions in the last 35 years due to bandhs and agitations you will find that this comes to an enormous figure. If we, sitting in Parliament and State legislatures, cannot protect our public property, we don't deserve to be in these Houses. So, I appeal to the Hon. Minister to apply his mind to see whether this legislation is sufficient; I am one of those who believe that this is not sufficient. But I would not like Dada ji, to shoot persons. You will have to apply your mind. Government is quite capable enough to take care of Government and public properties. I would like to know whether it is possible to treat all such people indulging in such activities as 'traitors' or 'Desh-ke-gaddar'. If it is done, I think, it will go a long way in protecting public property and in creating confidence among the people. Thank you.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : समपति महोदय, इस विल को देखने के बाद ऐसा लगा कि सरकार को कुछ चिन्ता है, सरकारी सम्पति को कुछ समझने लगी है। इससे पहले जैसे हिन्दुस्तान में काम हो रहें हैं, उससे यह लगता है कि सरकार उस फारमूले से काम कर रही है कि जो चीज सारे समाज की हो, वह किसी की नहीं होती, कोई उसकी रक्षा को आगे नहीं आता। ऐसा लगता है कि सरकार इसी सिद्वान्त पर काम कर रही थी।

सवाल यह है कि कुछ चीजें बची हुई हैं, उनकी रक्षा का एक तरीका आपने अधिक दंड का प्रावधान कर के निकाला, में यह पूछना चाहता हूं कि जो लोग सार्वजनिक सम्पति को कमजोर कर रहे हैं, जबर्दस्ती नुकसान पहुंचा रहे हैं, बड़े-बड़े पदों पर बैठकर, उनको वारे में आपका क्या सवाल है ? खाली सरकारी सम्पति को कोई आग न लगाये, डैमेज न करें यही बात नहीं है कि पिछले वर्ष श्री नारायण दत्त तिवारी एक पुल का उद्धाटन करने हलद्वानी गये। उस पुल का उद्धाटन करने के 15 निद के बाद वह पुल मय एक ट्रक के नीचे चला गया। यह सरकारी सम्पति और पब्लिक की प्रापर्टी का नुकसान है या नहीं ? इसकी क्या जिम्मेदारी आपने निकाली है ?

इसके लिए आप दंड की क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? कमजोर सड़कें और कमजोर विल्डिगें बना कर सरकारी मशीनरी द्वारा सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसे और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं।

सरकारी सम्पति को और तरीकों से भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दीवानी और माल के मुकदमों में सरकारी स्टैंडिग कौंसल दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं और सरकार मुकदमों में हार जाती है। इसकी रोक-थाम के लिए कोई अच्छा तरीका नहीं निकाला गया है। वे लोग क्रिमिनल केसिज में अपीयर ही नहीं होते देर कर देते हैं और अभियुकत छूट जाते हैं। नीचे के जजिज के लेवल पर बड़ी बड़ी सम्पतियों के मुकदमों चलते हैं, जिनमें सरकार इनवाल्ण्ड होती है। पैनल कौंसल गवर्नमेंट कौंसल और स्टैंडिग कौंसल की लापरवाही की बजह से सरकार की लाखों करोड़ों का सम्पति दूसरों का हाथ मे पहुंच जाती है। सरकार को इसके बारे में भी कुछ करना चाहिए था।

इनकम टैक्स और सेल्ज टैक्स का जो पैसा सरकार के पास आता है, वह भी सम्पति है। उसको भी आधे-आधे, फिफ्टी-फिफ्टी के बैसिस पर तय कर लिया जाता है और सरकार का नुकसान होता है।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : Sir, can he say all thess things ? Should he tell all these thing-only now or during the General Discuse sion on the Budget ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं यह कह रहा हूं कि सरकारी सम्पति वही नहीं है, जिसका इस बिल में जिक्र किया गया है। और भी सरकारी सम्पति है, जिसको लोग खा-पी रहे हैं, मगर सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है।

उस इंजीनियर को अपने क्या सजा दी, जिसने हल्दवानी में ऐसा पुल वनाया, जो मय ट्रक के गिर गया ? क्या वह सरकारी सम्पत्ति नहीं है ?

श्री एम. रामगोपाल रेडडी : क्या उन सब को इस बिल में लाया जाए ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : हम तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि सरकारी सम्पति क्या भी कुछ मूल्य होता है, यह आपने मान लिया। अब तक तो यह स्थिति रही है कि जो समाज की सम्पति है, वह किसीं की नहीं है. कोई उसकी रक्षा नहीं करता था। आपने कुछ किया है, तो धन्यवाद ही दूंगा।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

गांव सभा, जिला परिषद्, म्यूनिसिपल बोर्ड और कार्पोरेशन आदि की सम्पति की रक्षा के लिए आपके यहां कोई निश्चित कानून नहीं है। जो चाहे गांव सभा की सम्पति पर मकान बना लेता है, म्यूनिसिपल बोर्ड और कार्पोरेशन की जमीन पर कब्जा कर के मकान और दुकान बना लेता है। मुकदमा दस-बारह साल तक चलता रहता है, मगर उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। इसी तरह सीलिंग की सारी जमीन लोग हड़प गए हैं। यू०पी० में बड़े बड़े मगर-मछों की फाइलें ही गायब है। ये जमीनें हरिजनों को मिलनी चाहिए थीं।

गवर्नमेंट रोडवेज, डी०टी०सीसे० पुर्जे और पूरी बसें गायब कर दी जाती हैं। रेलवे का सामान रेल-कर्मचारियों से मिल दूसरे लोग ले लेते है। उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए इसी तरह सरकार का कोयला और सीमेंट वगैरह भी गायब होता रहता है।

किसान सम्मेलन के लिए और रिजर्वेशन के खिलाफ जलसा-जुलूस कराने के लिए सरकारी बसें फ्री भेजी जाती हैं। वह भी सरकारी सम्पति का दुरुपयोग है। बंगाल में फारूक अब्दुल्ला गए वहां उनकी कार पर आपके वर्कर्स ने ईंट पत्थर फेंके लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई। दूसरी ओर यहां हरियाणा में कर्नल राम सिह गवर्नर की गर्दन पकड़ लेते हैं तो उसके बाद उनके खिलाफ वारन्ट निकलता है जब तक कि अपोजीशन में रहते हैं, लेकिन जब कांग्रेस में चले जाते हैं तो मिनिस्टर भी बन जाते हैं और मुकद्दमा भी खारिज हो जाता है। परन्तु बंगाल में प्रेजाइडिंग आफिसर को कांग्रेस (इ) विधायकों ने पकड़ लिया लेकिन कुछ भी नहीं किया गया।

आज सरकारी सम्पत्ति को बुरी तरह से नष्ट किया जा रहा है लेकिन आपने एक तरफ ही थोड़ा सा ध्यान दिया है। हमारा यह आक्षेप है कि पहले जब आपने डी०आई०आर०, सीमा और एन० एस०ए० बनाए तब आपने कहा कि इनका राजनीतिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा लेकिन केरल में जब एन०जी० ओज और टीचर्स ने अपना बोनस लेने के लिए हड़ताल की तो इसी प्रकार के बिल के अन्तर्गत आपने उनको वहां पर अरेस्ट करके उन पर मुकद्दमे रजिस्टर कर लिए। हालांकि रिपोर्ट यह कह रही है कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन फिर भी वहां पर आपने उनके खिलाफ इसी प्रकार के कानून में केसेज दर्ज कर लिए। इस प्रकार से वहां आपने इससे पोलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की।

इस प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहां बरेली में सरकारी रूलिंग पार्टी के एक एम०एल०ए० हैं जो मिनिस्टर रह चुके हैं उनका लड़का ऐसा था जिसको डाकू नाम देने की जरूरत रह गई थी बाकी सारे दुर्गुण उसमें विद्यमान थे। उसको किसी ने मार दिया। उसके बाद तीन लड़कों पर मुकद्दमा कायम हो गया। डेढ़ साल के बाद उनकी जमानतें हुई लेकिन जिस दिन वे जेल से बाहर आए उनके अगले दिन ही एन०एस०ए० में उनको रख दिया गया क्योंकि उनमें एक लड़का सी० पी०एम० के वर्कर का लड़का था और मरने वाला कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री का लड़का था तो इस तरह से आप इन एक्ट्स

का दुरुपयोग करते हैं और आगे भी पार्टी पालिटिक्स में पड़कर इसका दुरुपयोग करेंगे यह हमारी आशंका है। इसीलिए हम अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। वैसे आप भी यहां पर किसी के इशारे पर ही काम कर रहे हैं, आपका अपना तो कुछ है नहीं। हो सकता है कि आप उधर रहें ही न जबकि इस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए उस वक्त आपके खिलाफ भी यह इस्तेमाल हो सकता है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश न करें। खास तौर से अभी जो आप सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करवा रहे हैं ठेके जारी करके इमारत, मशीन कारखानों के मामले में उनको आप ठीक करिए। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और यह देश ठीक से चले—यही प्रार्थना करते हुए मैं समाप्त करता हूं।

PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla): Mr. Chairman, Sir, the Bill has been worded in such a manner that it appears that it is something that is necessary, but personally speaking, I feel that this Bill is in insult to injury, not because the Ordinance was promulgated in January when the Parliament itself was meeting in February, but because there was no need to have further law on the subject. Shri Shailani has already left; in his innocence perhaps he was thinking that his Government has found this as a panacea and a lasting solution to the problem relating to the Government property.

I want to pose a question to the Minister: is he sure that the Indian Penal Code does not propose punishments to the crime that take place in this country? Before the very nose of the people responsible for enforcing law and order in the capital of this great country, murders, rape and bride-burning take place. Robberies and dacoities are there, and the law is there. But the enforcement of law is missing.

I do not propose to deliver a long speech. Nor is there time for it. The present Chairman, particularly, will not allow me time. Secondly. Shri Parulekar has made very valid points. I would sincerely pleased with the Minister to take notice of them, and withdraw the Bill, put up courage, put an exhibition of the will and a solid determination that the law already available with them will be enforced.

I wish Mr. Reddy and Mr. Shailani were here. I would remind that even last time when Government presented two Bills, viz. the Punjab (Disturbed Areas) Bill and the Chandigarh (Disturbed Area) Bill, although we welcomed those suggestions, we had told you that not because of those Bills which would become law the next day you passed them—if there was a will, you could solve the problem.

Before the Punjab (Disturbed Areas) Bill was passed, before the Chandigarh (Disturbed Area) Bill was passed, you saw that happened in Punjab. Your Government controlled media would inform us every evening those days, before the Bills were passed, that in such and such a street or *mohalla* in Amritsar, Gurdaspur and Pathankot or anywhere else in Punjab, such and such persons, men and women were murdered by people who were not identified. And that situation has continued after you passed those two Bills.

It is only yesterday that a police constable was murdered; and an Inspector was also injured. But again the same phrase was repeated, viz. that the person who opened fire was not identified. It is actually a great insult to present a Bill without any necessity. If the Hon. Minister rises, he will have in his right hand the Indian Penal Code and he will tell us that the law is not there. Can any one of us believe that there is no law to check robbery, murder or bride-burning? But every kind of crime is going on, and still you bring a piece legislation. It will certainly become an Act after you pass it, because you are

[Prof. Aaifuddin Soz]

in a majority. But please take note of what Mr. Parulekar said a few minutes ago.

I want to say that in such cases, you should rise above party considerations and see whose workers caused damage to public property in West Bengal. I was present there when Dr. Farooq Abdullah was attacked by Congress workers. The West Bengal Government took penal action against those who assaulted Dr. Farooq Abdullah. The next day, there was a demonstration by Congress workers, and property worth crores was damaged. What happened in Jammu and Kashmir ? Your Congress resorted to violence and put Government offices on fire. They held a lot of public property to ransom and caused great damage to public property, to private property. It was your government who could take action. When you preach us these sermons, you must search your soul and bring for ward a Bill only when it is necessary. But meanwhile I request the Hon. Minister to kindly rise to the occasion, put up your courage and an exhibition of will that is required in the Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : Mr. Chairman, I thank all the Hon. Members who have participated in the debate and also those hon. Members in whose speeches relevance was the first casualty. I would like to confine myself to the provisions of the Bill and various suggestions and criticisms that have been made by the hon. members who have participated in this debate.

The first criticism that has been made is why did the government resort to promulgation of an Ordinance and what was the urgency about it ? They said, promulgation of an Ordinance is a violation of the constitutional provisions. I may humbly inform the House that promulgation of an Ordinance is according to the Constitution; and we have come at the earliest moment before this August House to introduce a Bill in place of the Ordinance. They have also asked us what are the circumstances that have led to promulgation of such an Ordinance and bring forward such a type of Bill ? Everybody knows —I need not overemphasise the fact— that because of the various circumstances that have come up of late with regard to some agitation in Punjab and other parts of the country where public property is being attacked and damaged, the government thought that it is their bounden duty, moral duty and also the administrative duty to protect the property of the nation. Public property does not belong to any one individual; it belongs to the nation. So, I thought it will be in the fitness of the things if such Ordinance and Bill be brought before this House.

Some other doubt that has been raised is that what is the purpose of the Bill when there are enough provisions in the IPC with regard to damage to property. I have already said in my opening speed that a distinction has been made between a public property and a private property; and we have come forward with an idea that there a distinction should be made and more deterrent punishment should be given to such of those people who indulge in acts of arson, vandalism and also damage the public property. The existing provisions on mischief in IPC are inclusive of public property. In view of the fact that the agitators' wrath is concentrated on public property these days, it has been considered necessary to provide for stiffer punishment in respect of public property and that is why a distinction has been made.

Public property has been defined as property owned by either the Central Government or a State Government or a Local Authority or a Body Corporate of a Company in which the government has majority shares or any institution that may be notified for the purpose in which the government has made substan-

tial contribution. If the property is under the control or possessions of the government or any such body, it is again public property.

For damage to public property punishment is now enhanced. Ordinarily, punishment will be upto 5 years of imprisonment and fine and if the damage is to property of a specified kind like sewerage system, oil installations, public transport etc. there will be a minimum punishment of six months. If the damage is caused through fire or explosive, the minimum punishment will be one year and the maximum may be 10 years R.I.

These are the salient features, to make a distinction between public property. And, unfortunately some of the Opposition Members are obsessed with certain notions. Behind every measure that the Government brings in this House, they say, that there is a sinister motive or a political motive. I can assure the hon. Members of this House that there is no political motive behind this and I can assure some of our Members that it is not the intention of the Government to use this Bill to embarrass the Opposition parties or create problems for them.

Mr. Yadav also was telling about the Emergency, that during the Emergency his party was an elite one.

SHRI VIJAY KUMAR YADAV : That was a mistake on our part.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat) : That was the biggest mistake, and we do not mind admitting that also.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I am glad that they are accepting it. We take a their acceptance. (*Interruptions*)

But it does not lie for Mr. Yadav to talk about Emergency.

So, I only say, let us examine this purely on merits, whether this type of a bill is warranted under the circumstances. I only wanted to bring this to the notice of the hon. Members and some other Members who provoked me, that I should be courageous, rise above etc., etc. I have got enough courage, and I have spent my political life usefully, participated in several bundhs, and strikes, but not in violence and vandalism. Mr. Narsimha Reddy has clearly put it in its proper perspective. *Bandhs*, strikes, or protests are the legitimate duties of every individual in this country, more so of the political parties. Nobody under the Constitution and a Parliamentary democracy, nobody can object if peacefully a protest is made, if a procession is taken, if a *bandhs* is organised. It is the legitimate duty of a citizen of this country who should operate under the four corners of the Constitution. The difficulty comes in, when as I have said it in the objective, that it should not lead to unsocial or anti-social activities, vandalism, burning, destruction of public property etc. Only to stop this type of things, the Government has come forward with this type of a Bill.

Mr. Nair has spoken with regard to the forest wealth. wealth. Forest wealth, if it a Government forest, it is considered to be Government property. So technically it comes under the purview of this Bill.

Another point which the hon. Members are missing is in the various provisions of the Indian Penal Code it has been clearly defined, term 'mischief' and what punishment is given to such acts of offence and destruction of property. The Government has only now come forward to fix a minimum of imprisonment for a particular type of offence. It is made six months in one case and one year in another case. So, it is only fixation of a minimum of punishment. It has been clearly stated, that it is not only imprisonment, fine or both. So, there is no question of only awarding fine or imprisonment. So that point must be made clear.

SHRI N. K. SHEJWALKAR : What have you say about court ? Why do

you take away the power from the court ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Power from the courts is not that all taken away.

SHRI N. K. SHEJWALKAR : You leave it to the judgment of the court.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : The Magistrate or the presiding Judge has got the discretion. He may not even award the minimum imprisonment, he can give specific reasons and also he may award an imprisonment of less than six months or one year. It is already there.

Mr. Daga is a person who is an authority on these Bills. He goes through them very carefully. He wanted very rigorous punishment to be given to the offenders. He want to the extent of saying that those persons who indulge in such things should be shot even before they are tried. Section 425 lays down that if one causes destruction of any property etc. with intention to cause loss, to public or a person, commits mischief. The loss, therefore, is by way of damage to property. He asked why these have been specified. These have been spacified beeause they are the essential services. It does not mean that others are being left out.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : Instead of specifying this, why not only say, if anybody commits on offence against public property, he shall be punished ? Where is the necessity of specifying this ? You are making a distinction. Kindly consider this.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I will again emphasise that this Act does not cover private property. For private property, under IPC the existing laws will apply. Here we are dealing with public property only. The court always has the discretion to fix up this type of imprisonment.

The other hon. Members have also spoken. Mr. Balanandan, my esteemed friend and a very respected Member of the CPM, stretched it too much. He was trying to make out a political case of this most innocent and simple legislation, which is being brought forward in the national interest.

Mr. Shastri and other Members have also participated. I congratulate Mr. Shastri for his oratory and eloquence in the speeches. But the points which he has made out are not relevent to the present Bill.

SHRI N. K. SHEJWALKAR : You have said in the clause 'oppose the application'. That opportunity is always there. Why are you putting it there. That means it is now mandatory to oppose even though there may not be a case.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : This is a point which has to be examined.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : According to you if the prosecution concedes, no bail shall be granted. If he says he does not oppose, therefore, no bail shall be granted.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : It is not like that.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : You do not mean that but your Section means that.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I would only appeal to the hon. Members that we have to give a fair trial to this Bill and it is with best of intentions that this Bill has been brought.

SHRI N. K. SHEJWALKAR : Court interprets in other way.....

(Interruptions)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : Your good intentions are not reflected in the Bill.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I cannot crosswords with eminent lawyers. The whole difficulty is I am not a lawyer, I am only a man of common-sense.

Sir, Prof. Ranga has told me, of course in private, that it will apply to the joint stock companies.' I may inform Prof. Ragaji that such of these joint stock companies where the Government shareholding is more than 51 per cent, will also come under the purview of this Bill.

So, I once again thank all the hon. Members for their valuable suggestions and as I have said, let us all give a fair trial to this Bill. Let the Opposition give all their cooperation in putting down this sort of anti-social activity and vandalism and destruction to property. I hope I elicit their cooperation in implementing this Bill in its full spirit.

SHRI K. T. KOSALRAM (Tiruchendur) : Forest is a Government property. There is a separate Act which provides that private forests must also get the permission from the Government. I want to know whether this Act is applicable to the private forests also or not ?

MR. CHAIRMAN : Shri Satyanarayan Jatiya.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I request Shri Jatiya to withdraw the Resolution.

श्री सत्य नारायण जटिया : सभापति महोदय, मैंने इस अध्यादेश और विधेयक पर हुई चर्चा को सुना है। मंत्री महोदय ने इसके जो आशय और सिद्धांत बताए हैं, लेकिन इस विधेयक से इस तरह की भावना अभिप्रेत नहीं होती। अगर भावनाओं और आशय, सिद्धांतों और नीतियों से सारी बात हो जाती तो इस विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

आपने एक्सप्लेनेसन दिया है और अपनी बात की व्याख्या करने की कोशिश की है। किन्तु बहुत सारी बातें छूट गई हैं। 436 में बताया गया है कि इस तरह का नुकसान करने के लिए आजीवन कारावास की भी व्यवस्था है। आपने कहा है कि पंजाब की स्थिति को नियंत्रित करने में इससे मदद मिलेगी। मेरा मतलब यह है कि अगर यह कारगर होता है तो ठीक है लेकिन अगर कारगर नहीं होता है तब आप क्या करेंगे ?

(व्यवधान)

6 महीने की अवधि बिनियम हो सकती है, इसकी व्याख्या करने की भी कोशिश की है। फिर आपने न्यायाधीश पर छोड़ दिया है कि वह कम भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है ? न्यायाधीश अपने विवेक के अनुसार कानून का पालन करवाता है। जब सारा प्रावधान है तो फिर विधेयक की क्या आवश्यकता थी ? अध्यादेश की क्या आवश्यकता थी ?

आपने कहा है कि इसके माध्यम से एन्टी सोशल एक्टीविटीज से सरकारी संपत्ति के नुकसान को रोका जाएगा। यह

[श्री सत्यनारायण जटिया]

कानून इसके लिए सक्षम नहीं है। एक असक्षम कानून से आप कैसे काम कर पायेंगे इसलिए मेरा कहना है कि यह कानून अधूरा है। इस पर पूरे तरीके से विचार किया जाए और इसको सलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। जब इस पर अच्छी तरह से विचार करके इसको लाया जागगा तब उद्देश्य की पूर्ति होगी।

18.00 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

इसको अच्छी तरह से विचार करके लायेंगे तो आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी। यह आशंका व्यक्त की गई कि श्रमिक गतिविधियों को इस कानून से प्रतिबंधित करने के लिए इसको लाया गया है। अगर यह कि विपक्षी दलों को सामने रखकर यह लाया गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इस प्रकार के कानूनों का दुरुपयोग ही हुआ है। आप इसको निर्मूल नहीं कर पाते। यहां कहने और करने में काफी अन्तर है। आज राजीतिक चरित्र का यह दोष है। आप के ऊपर मंत्री पद का दायित्व भी है इसलिए इस प्रकार की बातों को कहना होता है। यह अध्यादेश उपयुक्त नहीं होगा। मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. DEPUTY SPEAKER : I will now put the Statutory Resolution to the vote of the House. The question is :

"This House disapproves of the Prevention of Damage to Public Property Ordinance, 1984 (Ordinance No. 3 of 1984) promulgated by the President on the 28th January, 1984."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill to provide for prevention of damage to public property and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER : We will now take up clause by clause consideration. The question is :

"That clause 2 to 7 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 2 to 7 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I beg to move :

"That the Bill be passed"

MR. DEPUTY SPEAKER ; The question is ;

"That the Bill be passed"

The motion was adopted.